RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 02, अंक 10 मासिक पत्रिका
25 अक्टूबर 2023

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

बिस चुनाव 2023

पांच चुनावी राज्यों में किस पार्टी के कितने विधायक

« समलैंगिक विवाह
पर आया अदालती फैसला भारतीय संस्कृति
भारतीय परम्पराओं व भारतीयता की जीत

ड्रोन परीक्षण »
कामयाबी हासिल करने वाला भारत पहला देश,
हर अध्ययन के बाद तैयार हो रही एसओपी

हमारा देश हमारा
अभिमान परिवार की ओर
से नवरात्र उत्सव की

हार्दिक
शुभकामनाएं

हमारा देश
हमारा अभिमान

25 अक्टूबर 2023

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडों कमल किशोर (पूर्व सांसद)

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक
और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
• सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी । (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश-प्रदेश	.....	06-07
देश	.....	08-09
देश	.....	10-11
उप्र	.....	12
राजस्थान	.....	11
प्रदेश	.....	12
रिकॉर्ड	.....	13
देश	.....	14
हमारा ग्वालियर	.....	14-22
राजस्थान	.....	23
जन्माष्टमी विशेष	.....	24-25
राजस्थान	.....	20-21
राजस्थान	.....	22-23
प्रदेश	.....	26
गौरव	.....	27
देश	.....	28-29
प्रदेश	.....	30-31
हमारा ग्वालियर	.....	32
प्रदेश	.....	34-35
देश-विदेश	.....	37
सेहत	.....	40-41
धर्म	.....	42-43
ग्लैमर	.....	46-47

निखिल कामथ को डेट कर रही हैं रिया **46**

संपादकीय

इस बार तीन राज्यों में मतदाताओं द्वारा चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे

पांच राज्यों मैं विधान सभा चुनावों का शंखनाद हो गया है। यह राज्य है मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना,और मिजोरम। इनमे से तीन हिंदी राज्य इन चुनावों मैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंग, क्योंकि इन राज्यों के परिणाम लोकसभा चुनावों मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जो की कुछ महीनो के बाद 2024 मैं होने है। यदि मैं अपने अनुभव और अपनी टीम के सर्वे के अनुसार कहूं तो इस बार भारती जनता पार्टी (बी जे पी) को मतदाता राष्ट्रयबाद और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही चुनावों का केंद्र बिंदु मानकर चलेंगे। जहां राष्ट्रवाद के साथ साथ देश की सुरक्षा, हिंदू धर्म का सम्मान भी महत्वपूर्ण और चुनावों की दिशा निश्चित करने मैं मुख्य भूमिका के रुप मैं अपना योगदान निभाएंगे। मेरे द्वारा किए गए तीन हिंदी राज्यों मैं मतदाताओं के द्वारा चौकाने ने वाले परिणामों नजर आएंगे। जहां अन्य न्यूज चैनलों , प्रिंट मीडियाओ की माने तो यह राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश मैं बी जे पी को कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर मैं बता रहे है । लेकिन मैं यह कहूं की इस बार शायद ही इन तीन राज्यों मैं चुनावों मैं कांग्रेस बी जे पी के कही भी आसपास नजर आए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। मेरे द्वारा कही गई इस बात की पुष्टि और तथ्य कांग्रेस पार्टी का और इनके गठबंधन आई एन डी आई या इंडी गठबंधन का हिंदू विरोधी सोच ,कार्य, भाषण ही इनके सरकार बनाने मैं बहुत बड़ी खाई की भूमिका निभाएगा, क्योंकि जनता या भारत के बोटर या इन राज्यों के मतदाता इनसे नफरत करने लगा है। बही दूसरी ओर मतदाता पी एम मोदी और भारती जनता पार्टी को अपने नजदीक पाता है। जहां मध्यप्रदेश मैं बी जे पी पहले की अपेक्षा अच्छा और चौकाने वाले परिणाम लाएगी बही छत्तीसगढ़ और राजस्थान मैं बी जे पी हिंदू मतदाताओं के साथ कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी यह सर्वे मैं निकल कर आया है जो मैने और मेरी टीम के द्वारा एकत्रित किए गए मतदाताओ से एक आम आदमी के रुप मैं एकत्रित किए गए है उस आधार पर बी जे पी ओर पी एम मोदी जी का चेहरा और गारंटी कांग्रेस के गढ़ों को ध्वस्त करते हुए बहुत से इन तीन राज्यों के विधानसभा के चुनावों का परिणाम अपने नाम करेगी । आगे फिर मत्तदान के परिणामों तक रुकना और इंतजार करना होगा।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

सनातन धर्म पर वार और अपमान इंडी गठबंधन को भारी पड़ने जा रहा है

पांच राज्यों मैं होने वाले चुनावो के परिणाम फिर रेवड़ी कल्चर को नकारेगे खासकर हिंदी राज्यों मैं राष्ट्र वाद और हिंदू अस्ति स्वाभिमान बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इन चुनावो में इंडी गठबंधन अपने गलत बयान बाजी, एक विशेष वर्ग के प्रति प्रेम,पी एम मोदी जी का अपमान, सनातन धर्म पर बार और अपमान इंडी गठबंधन को भारी पड़ने जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी को पतन की ओर ले जायेगा। राहुल गांधी , कांग्रेश पार्टी के नेताओ के साथ साथ इंडी गठबंधन के नेताओ की भाषा कांग्रेस के पतन की रुप रेखा लिखेगी क्यों की मतदाता बहुत ही जागरुक हो गया है। और वो रेवड़ी कल्चर सेबहुत परिचित हो गया है। वह राष्ट्र वाद और सनातन धर्म का अपमान किसी भी प्रकार से अपमान स्वीकार कर सकता।

जय हिंद

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

पिछले विधानसभा चुनाव से कितने बदले समीकरण?

पांच चुनावी राज्यों में किस पार्टी के कितने विधायक

पांच चुनावी राज्यों में कुल 679 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। वहीं, राजस्थान में 200 तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 678 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। राजस्थान में एक सीट पर प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव नहीं हो सका था।

सभी 678 सीटों में से सबसे ज्यादा 305 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। वहीं, भाजपा के खाते में 199 सीटें आईं थीं। दोनों ही पार्टियों ने सभी पांच राज्यों में चुनाव लड़ा था। सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर तेलंगाना की टीआरएस रही थी। के चंद्रशेखर राव की पार्टी को 88 सीटों पर जीत मिली थी। टीआरएस ने चुनाव के बाद सत्ता में दोबारा वापसी की थी। इसी तरह मिजोरम में चुनाव जीतने वाली एमएनएफ सीटों के लिहाज से चौथे नंबर पर रही थी। उसी कुल 26 सीटों पर जीत मिली थी। पांच राज्यों में कुल 26 निर्दलीय भी जीते थे। सबसे ज्यादा 13 निर्दलियों को राजस्थान में जीत मिली थी। बसपा भी दहाई का आंकड़ा छूने में सफल रही थी। उसे तीन राज्यों में कुल 10 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें से छह सीटें राजस्थान तो दो-दो सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की थीं।

2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलियों के अलावा 14 राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जीतने में सफल रहे थे। अन्य दलों में एआईएमआईएम को सात, जेसीसी को पांच, रालोप को तीन, टीडीपी, बीटीपी, माकपा को दो-दो और

फॉरवर्ड ब्लॉक, सपा और रालोद एक-एक सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे।

कांग्रेस की सीटें घटीं, BJP-TRS व MNF की बढ़ीं

चुनाव के बाद कहीं दल बदल तो कहीं विधायकों के निधन की वजह से उप-चुनाव हुए। राजस्थान में तो बसपा के सभी छह विधायकों ने विधायक दल को कांग्रेस में शामिल करा लिया। इस वजह से पार्टियों की सीटों में काफी बदलाव हो चुका है। चुनाव घोषणा से पहले तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक-एक सीट रिक्त थी। इस तरह कुल 676 सीटों में से सबसे ज्यादा 285 सीटें कांग्रेस के पास थीं। हालांकि, उसकी सीटों की संख्या में 20 सीटों की गिरावट आई है। बसपा की सीटें भी 10 से घटकर चार रह गईं। वहीं, भाजपा की सीटें 199 से बढ़कर 214 हो गईं। इसी तरह 2018 में 88 सीट जीतने वाली टीआरएस की सीटें बढ़कर 101 हो गईं तो एमएनएफ सीटें 26 से बढ़कर 28 हो गईं हैं।

राजस्थान के रण में क्या हुआ?

राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। राज्य में चुनाव नतीजे 11 दिसंबर 2018 को घोषित किए गए थे। अलवर की रामगढ़ सीट छोड़कर बाकी 199 सीटों पर मतदान हुआ। रामगढ़ सीट पर बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देते हुए 99 सीटें जीतीं। इसके साथ ही प्रदेश में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहा। भाजपा को 73, मायावती की पार्टी बसपा को छह तो अन्य को 20 सीटें मिलीं। कांग्रेस को बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत थी। कांग्रेस ने निर्दलियों और अन्य की मदद से जरूरी आंकड़ा जुटा लिया। इसके साथ ही राज्य की सत्ता में वापसी की और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में राजस्थान के सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 108, भाजपा के 70 और 21 अन्य हैं। वहीं एक सीट रिक्त है।

कैसे बदले समीकरण?

मध्यप्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुआ था। चुनाव नतीजे 11 दिसंबर 2018 को आए थे। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से दो कम 114 सीटें मिलीं थीं। वहीं, भाजपा 109 सीटों पर आ गई। हालांकि, यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिला था। बसपा को दो जबकि अन्य को पांच सीटें मिलीं। नतीजों के बाद कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में मध्यप्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें तो 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय चार, दो बसपा और एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।

छत्तीसगढ़ की सियासत कितनी बदली?

2018 में राज्य में दो चरणों मतदान कराए गए थे। पहले चरण का मतदान 12 नवंबर 2018 और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। चुनाव नतीजे आए तो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 और भाजपा को 15 सीटें मिलीं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने पांच सीटें जीते थीं और दो सीटें बसपा के खाते में गई थीं।

तेलंगाना की सियासत में क्या-क्या घटा?

राज्य में पिछले चुनाव सात दिसंबर 2018 को हुए थे। 2018 में राज्य में सात दिसंबर 2018 को चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। इस चुनाव में 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, आईएमआईएम को सात, टीडीपी को दो, भाजपा को एक, एआईएफबी को एक सीट मिली थी। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली थी। इस वक्त 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस के 101, एआईएमआईएम के सात, कांग्रेस के पांच, भाजपा के तीन और एआईएफबी के एक विधायक हैं। एक सीट पर निर्दलीय विधायक है, जबकि एक सीट अभी खाली है।

मिजोरम की राजनीति कैसी रही?

राज्य में पिछले चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा में एमएनएफ को 27 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने चार सीटें, जबकि भाजपा को एक सीट पर विजय मिली थी। इसके अलावा आठ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व में एमएनएफ की सरकार बनी थी। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखें तो, इस वक्त 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में एमएनएफ के 28, कांग्रेस के पांच, जेडपीएम के एक और भाजपा के एक विधायक हैं। पांच सीट पर निर्दलीय विधायक हैं।

समलैंगिक विवाह

पर आया अदालती फैसला भारतीय संस्कृति भारतीय परम्पराओं व भारतीयता की जीत

हम आपको यह भी बता दें कि सुनवाई के समय जहां एक ओर अदालत में समलैंगिक विवाह के पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी जा रही थीं उसी समय देश के चौक-चौराहों, चौपालों और घर-घर में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी।

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर उच्चतम न्यायालय ने वाकई ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। देखा जाये तो अदालत का फैसला भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्पराओं और भारतीयता की जीत है। अदालत का फैसला भारतीय जन भावनाओं की पुष्टि भी करता है साथ ही एक सख्त संदेश उन विदेशी ताकतों को भी देता है जोकि भारत का सामाजिक चरित्र बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, हमारे धार्मिक, सामाजिक और नागरिक संगठन भी सराहना के पात्र हैं क्योंकि इन सभी ने संयुक्त रूप से भारतीय वैवाहिक और सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ी और उसमें विजयी रहे।

जहां तक उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात है तो आपको बता दें कि पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बारे में कानून बनाने का काम संसद का है। हम आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी 21 याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की थी। फैसला सुनाते समय प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता, बल्कि उनकी केवल व्याख्या कर सकता है और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है।

हम आपको यह भी बता दें कि सुनवाई के समय जहां एक ओर अदालत में समलैंगिक विवाह के पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह की दलीलें दी जा रही थीं उसी समय देश के चौक-चौराहों, चौपालों और घर-घर में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। चूंकि आम भारतीय की नजर में

समलैंगिकता को एक 'विकार' माना जाता है इसलिए तर्क दिया जा रहा था कि यदि समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता मिलेगी तो समाज गलत दिशा में जायेगा। यह भी कहा जा रहा था कि समलैंगिक माता-पिता बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे।

हम आपको यह भी बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं ''शहरी संभ्रांतवादी'' विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं और विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए। सरकार के ही पक्ष का बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने भी समर्थन किया था। बार काउन्सिल ने उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक विवाह मुद्दे की सुनवाई किये जाने पर चिंता जताते हुए कहा था कि इस तरह के संवेदनशील विषय पर शीर्ष न्यायालय का फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है इसलिए इसे विधायिका के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि बार काउन्सिल के बयान का तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने विरोध किया था। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिये जाने के पक्ष में पहले से ही खड़े थे। लेकिन ढेरों राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक और धार्मिक संगठन आदि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिये जाने के खिलाफ डटे हुए थे और अब उच्चतम न्यायालय का फैसला सामने आने के बाद सभी उसका हृदय से स्वागत कर रहे हैं।

वैसे जो लोग समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिये जाने के पक्ष में खड़े थे या अब भी खड़े हैं उन्हें समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में शादी केवल यौन सुख भोगने का एक अवसर नहीं है। विवाह द्वारा शारीरिक संबंधों को संयमित रखने, संतति निर्माण करने, उनका उचित पोषण करने, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने और अपनी संतति को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने जैसे जिम्मेदारी भरे कार्य भी किये जाते हैं। इसके अलावा, यदि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाती तो कल को यह भी हो सकता था कि समलैंगिक संबंध वाले अपने आप को लैंगिक अल्पसंख्यक घोषित कर अपने लिए आरक्षण की मांग कर देते।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ था?

इस मामले की शुरुआती सुनवाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि भारत समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर इतिहास बनाने के क़रीब है। चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की संवैधानिक खंडपीठ ने कहा था कि वह धार्मिक व्यक्तिगत क़ानूनों में दख़ल नहीं देगी लेकिन इस बात पर विचार किया जाएगा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को मान्यता देने वाले विशेष क़ानून में बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं।

लेकिन जैसे-जैसे अदालती कार्यवाही आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होता चला गया कि मामला कितना पेचीदा है। पाँच जजों की खंडपीठ ने माना कि सिर्फ़ एक क़ानून में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि तलाक़, गोद लेने, उत्तराधिकार और गुज़ारा देने जैसे अन्य क़रीब 35 क़ानून हैं जिनमें से कई धार्मिक व्यक्तिगत क़ानूनों के दायरे तक जाते हैं।

समलैंगिक समुदाय का क्या था तर्क

याचिकाकर्ताओं के वकीलों का तर्क था कि शादी दो लोगों का मिलन है, न कि सिर्फ एक महिला और पुरुष का। ऐसे में उन्हें शादी करने का अधिकार न देना संविधान के ख़िलाफ़ है क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है और सेक्शुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शादी न कर पाने के कारण इस समुदाय के लोग न तो संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं, न घर के साझे मालिक बन सकते हैं औ न ही बच्चों को गोद ले सकते हैं. वे शादी के साथ मिलने वाली इज़्ज़त से भी महरूम हैं। वहीं, एलजीबीटीक्यू समुदाय को शादी की समानता देने का कड़ा विरोध कर रही सरकार का कहना था कि शादी के इस सामाजिक-क़ानूनी विषय पर सिर्फ़ संसद चर्चा कर सकती है और अदालत को इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं है। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि प्यार करने और साथ रहने का अधिकार बुनियादी है मगर शादी एक 'संपूर्ण अधिकार नहीं है' और यह बात विषमलैंगिक (महिला-पुरुष) जोड़ों पर भी लागू होती है।

विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर रिश्तेदारों के बीच मुकाबला

पार्टी कार्यकर्ता इस परिवार का हिस्सा हैं। पार्टी एक उपयुक्त कार्यकर्ता को मैदान में उतारने के बारे में निर्णय करती है। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है जहां सभी प्रमुख निर्णय एक परिवार द्वारा लिया जाता है जबकि भाजपा एक कैडर-आधारित संगठन है।

मध्यप्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक ही परिवार के सदस्यों के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने रिश्तेदारों को टिकट देकर सत्ता की तलाश में एक-दूसरे से मुकाबले में खड़ा कर दिया है।

प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में भाई, चाचा-भतीजा, देवर-भाभी, समधि आदि निकट एवं दूर के रिश्तेदार आमने-सामने खड़े हो गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नर्मदापुरम से भाजपा उम्मीदवार सीताशरण शर्मा का मुकाबला उनके भाई गिरिजाशंकर शर्मा से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भाजपा के पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने हाल ही में अपनी पार्टी बदल दी और सत्तारूढ़ दल द्वारा टिकट देने से इनकार करने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। सागर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की निधि सुनील जैन का मुकाबला अपने जेठ और मौजूदा भाजपा विधायक शैलेन्द्र जैन से है।

निधि जैन, शैलेंद्र जैन के छोटे भाई और देवरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्नी हैं। इसी तरह रीवा जिले के देवतालाब में कांग्रेस ने पद्मेश गौतम कोभाजपा विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ मैदान में उतारा है, गिरीश गौतम पद्मेश के चाचा हैं। पद्मेश गौतम ने इससे पहले पंचायत चुनाव में मौजूदा विधायक के बेटे राहुल गौतम को हराया था। एक अन्य अंतर-पारिवारिक चुनावी लड़ाई में मौजूदा भाजपा विधायक और पार्टी उम्मीदवार संजय शाह हरदा जिले के टिमरनी में अपने भतीजे कांग्रेस के अभिजीत शाह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभिजीत शाह दूसरी बार अपने चाचा के खिलाफ मैदान में हैं। ग्वालियर जिले के डबरा में भाजपा की पूर्व राज्य मंत्री इमरती देवी अपने रिश्तेदार और मौजूदा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे से मुकाबला कर रही हैं।

भाजपा सूत्रों ने कहा कि इमरती देवी की भतीजी की शादी राजे के परिवार में हुई है। इन सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ रिश्तेदारों को मैदान में उतारने के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पीटीआई से कहा, मध्यप्रदेश भाजपा के लिए एक परिवार है। पार्टी कार्यकर्ता इस परिवार का हिस्सा हैं। पार्टी एक उपयुक्त कार्यकर्ता को मैदान में उतारने के बारे में निर्णय करती है। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है जहां सभी प्रमुख निर्णय एक परिवार द्वारा लिया जाता है जबकि भाजपा एक कैडर-आधारित संगठन है।

रिश्तेदार बनाम रिश्तेदारों की चुनावी लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने इसे महज संयोग बताया। मिश्रा ने कहा, '' अलग-अलग विचारधारा वाले लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो यह संयोग चुनावी मैदान में भी हो सकता है।''

उन्होंने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रतियोगियों के बीच वसुधैव कुटुंबकम (दुनिया एक परिवार है) की भावना बनी रहनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति के जानकार आनंद पांडे ने कहा कि यह विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि सत्ता और पद पाने की लड़ाई है।

उन्होंने कहा कि राजनीति नई दिशा में जा रही है। दोनों शर्मा भाई (सीताशरण और गिरिजाशंकर) नर्मदापुरम में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा विधायक थे और उनमें से एक अब दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह सागर, टिमरनी और देवतालाब में भी परिवार के करीबी सदस्य एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पांडे ने कहा, '' राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाइयों और करीबी रिश्तेदारों ने राजनीति और सत्ता के खेल को अपने संबंधों से ऊपर रखा है।''

पांडे ने कहा कि पहले एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग पार्टियों में होते थे, लेकिन विधानसभा में प्रवेश के लिए उनके बीच सीधी लड़ाई दुर्लभ थी। मध्यप्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।

मंडल आयोग व आर्थिक उदारीकरण : पिछड़े वर्गों के लिए क्या बदलाव..?

विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा अगस्त 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने (जिसकी वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को आरक्षण में हिस्सेदारी मिली) की घोषणा के 11 महीने बाद पी वी नरसिंह राव सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ाए। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े और सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए सरकारी नौकरियां ही प्राथमिक वाहक नहीं रहीं। निश्चित रूप से आर्थिक उदारीकरण ने सरकार का राजस्व बढ़ाने में मदद की। उसने केंद्रीय और राज्य सरकारों को समाज कल्याण के लिए और अधिक धन मुहैया कराया। उदाहरण के लिए मौजूदा सरकार का कहना है कि उसकी कई कल्याण योजनाएं मसलन मुद्रा योजना के लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और महिलाएं हैं। आर्थिक उदारीकरण ने अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कौशल आधारित रोजगार भी तैयार किए हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पूर्व समाजवादी पार्टियों के विभिन्न अवतारों में शीर्ष पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं की उपस्थिति बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव को अपनाने में कांग्रेस की तुलना में अधिक तेजी दिखाई। मंडल ने उत्तर और पश्चिम भारत की राजनीति को बदल दिया। दक्षिण भारत के राज्य यह प्रक्रिया सन 1960 के दशक से ही देख रहे थे।

बहरहाल, मंडल आयोग से मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की रसूखदार जातियां लाभान्वित हुईं। देश की शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत का अर्थ यह था कि इन जातियों में भी जो लोग हाशिये पर थे उन्हें आर्थिक उदारीकरण के लाभों को हासिल करने लायक कौशल हासिल नहीं हो सका। इस बीच अन्य पिछड़ा वर्ग में राज्य और केंद्र की सूचियों में 1990 के बाद से काफी इजाफा हुआ है। हाल के वर्षों में मराठा जैसी कई जातियां इस सूची में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरीं। सामाजिक न्याय की हिमायत करने वाले नेताओं ने मांग की है कि आरक्षण को निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए या फिर यह भी कि अब वक्त आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के लिए तय 50 फीसदी की सीमा को भंग किया जाए। बल्कि 2017 में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग का गठन किया ताकि आरक्षण के फॉर्मूले को नए तरीके से परखा जा सके और उसने अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की उप श्रेणियां बनाने की अनुशंसा की। परंतु पिछड़ा वर्ग की आबादी के विश्वसनीय आंकड़े नहीं होने के कारण नीतिगत निर्णय प्रभावित हुए। आखिरी जाति जनगणना सन 1931 की जनगणना में हुई थी। मंडल आयोग ने उस आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया था कि देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 52 फीसदी होगी। बिहार में हुआ जाति सर्वेक्षण उस कमी को दूर करता है। संभावना यही है कि अन्य राज्यों में भी इसका अनुकरण किया जाएगा या फिर जाति जनगणना ही होगी।

बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां की आबादी में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 63 फीसदी है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अति पिछड़ा वर्ग, दर्जनों बंटी हुई छोटी जातियां 36 फीसदी हैं। पिछड़ा वर्ग में 12.9 फीसदी मुस्लिम हैं। 15.52 फीसदी सामान्य आबादी में 4.8 फीसदी मुस्लिम हैं। राजनीतिक तौर पर इस बात का जोखिम है कि जाति गणना में समस्या से और अधिक ध्रुवीकरण हो सकता है तथा इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। बहरहाल, समय के साथ जैसा कि मंडल राजनीति ने दिखाया भी भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों को अपनी राजनीतिक रणनीति को नए परिदृश्य के मुताबिक बदलना होगा। इस संदर्भ में जाति आधारित कोटा पर 50 फीसदी की सीमा को लेकर निश्चित रूप से विवाद होगा। जिन जातियों को मंडल आयोग का लाभ नहीं मिला वे अपनी हिस्सेदारी मांगेंगी। परंतु जैसा कि भारतीय इतिहास बताता है वास्तविक प्रगति तेज आर्थिक वृद्धि और शिक्षा एवं तकनीक में निवेश के जरिये ही हो सकती है ताकि जनांकिकीय लाभ हासिल किया जा सके। राजनीतिक वर्ग को केवल आरक्षण के माध्यम से सशक्तीकरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पिछड़ा वर्ग का वास्तविक सशक्तीकरण केवल तभी होगा जब राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लाभप्रद रोजगार दिला सकेगा। जाति सर्वेक्षण या अधिक आरक्षण अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं हो सकते।

केंद्र का एलान

हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह फैसला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह फैसला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए की गई है। इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी की गई गई है।

अंतरिक्ष विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, '23 अगस्त, 2023 को विक्रम लैंडर की लैंडिंग और चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान -2023 मिशन की सफलता के साथ भारत अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया, जो चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला राष्ट्र बन गया। इस ऐतिहासिक मिशन के परिणाम आने वाले वर्षों में मानव जाति को लाभान्वित करेंगे।'

इसमें आगे कहा गया, यह दिन अंतरिक्ष मिशनों में देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है और अंतरिक्ष क्षेत्र को एक प्रमुख प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए, भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक क्षण को मनाने के लिए हर साल अगस्त के 23वें दिन को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में घोषित किया है।

एफएओ रिपोर्ट में आया सामने

आपदाओं से किसानों को 316 लाख करोड़ का नुकसान...

रिपोर्ट के अनुसार, आपदाओं से कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान एशिया में पहुंचा है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की बारी आती है। हालांकि, जहां एशिया में यह नुकसान कृषि मूल्य का केवल चार फीसदी था, वहीं अफ्रीका में वह करीब आठ फीसदी था।

किसानों को पिछले तीन दशक में प्राकृतिक आपदाओं के कारण करीब 316.4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों को हर साल फसलों और मवेशियों के रूप में औसतन 10.24 लाख करोड़ रुपये की चपत लग रही है। यह कृषि के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब पांच फीसदी है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की नई रिपोर्ट 'द इम्पैक्ट ऑफ डिसास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी' में यह बात सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 30 वर्ष में हर वर्ष औसतन 6.9 करोड़ टन अनाज का नुकसान हो रहा है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह नुकसान 2021 में फ्रांस में अनाज की कुल पैदावार के बराबर है। इसी तरह फल, सब्जियों और गन्ने की फसलों में सालाना करीब चार करोड़ टन का नुकसान दर्ज किया गया, जो तुलनात्मक रूप से 2021 में जापान और वियतनाम में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के बराबर है। इन आपदाओं से हर वर्ष औसतन 1.6 करोड़ टन मांस, अंडे और डेयरी उत्पाद बर्बाद हो रहे हैं।

एशिया में सबसे अधिक बर्बादी

रिपोर्ट के अनुसार, आपदाओं से कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान एशिया में पहुंचा है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की बारी आती है। हालांकि, जहां एशिया में यह नुकसान कृषि मूल्य का केवल चार फीसदी था, वहीं अफ्रीका में वह करीब आठ% था।

रोजाना 22% कैलोरी की कम

एफएओ का कहना है कि आपदाओं के कारण दुनिया पहले ही चार फीसदी संभावित फसल और पशुधन उत्पादन गवां चुकी है। यह नुकसान प्रतिवर्ष 6.9 ट्रिलियन किलो कैलोरी अथवा 70 लाख वयस्कों की वार्षिक कैलोरी सेवन के बराबर है। अगर इस नुकसान की व्याख्या गरीब, निम्न और मध्यम आय वाले देशों के संदर्भ में की जाए तो यह रोजाना 22 फीसदी कैलोरी की कमी है।

भारत की स्थिति

भारत में हाल के वर्षों में फसल के नुकसान पर संसद में सरकारी उत्तरों से एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 से भारी बारिश और बाढ़ सहित मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 3.60 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। वहीं, 2016 में 60.65 लाख हेक्टेयर पर फसलों को पहुंचे नुकसान का अनुमान 4,052.72 करोड़ रुपये था। यदि इसे 2016 से 3.60 करोड़ हेक्टेयर फसली क्षेत्र पर लागू कर दिया जाए तो यह 29,939 करोड़ रुपये के भारी नुकसान के रूप में परिलक्षित होता है।

गृहमंत्री ने कहा- 1984 के दंगे नहीं भूल सकते

अमित शाह बोले- 300 मामले खोले, दोषियों को भेजा जेल

गृह मंत्री शाह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार यह तय करेगी कि जो भी मामले चल रहे हैं, उनमें पीड़ितों को इंसाफ मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी सभ्य व्यक्ति 1984 के दंगे नहीं भूल सकता। राजनीतिक इशारे पर नृशंस हत्याएं की गईं लेकिन, किसी दोषी को सजा नहीं दी गई। 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद दंगे के 300 मामलों को फिर से खोला गया और दोषियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार यह तय करेगी कि जो भी मामले चल रहे हैं, उनमें पीड़ितों को इंसाफ मिले। मोदी सरकार ने ही पहली बार 3,328 पीड़ित परिवारों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये देने और जलिया वाला बाग स्मारक को फिर से गौरवान्वित करने का काम किया है।

मानवता के लिए सिख गुरुओं के बलिदान की बराबरी नहीं

शाह ने कहा, मानवता और देश के लिए सिख गुरुओं के बलिदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सिख पंथ के अलावा ऐसा कोई दूसरा पंथ नहीं, जिसने 10 पीढ़ियों तक आक्रांताओं के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए बलिदान दिया हो। औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 9वें गुरु तेग बहादुर को देश हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर की स्मृति में लाल किले पर ठीक उसी जगह उत्सव मनाने का फैसला किया, जहां उनकी शहीदी की घोषणा हुई थी।

गृहमंत्री शाह बोले- सिख कौम हमेशा सबसे आगे रही

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरफ से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत की आजादी के आंदोलन, मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, विभाजन की विभीषिका या आजादी के बाद देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, सिख कौम हमेशा सबसे आगे रही है। हमारा आजादी के संघर्ष का इतिहास सिख बहादुरों के बलिदान से भरा पड़ा है और देश के आजाद होने के बाद इसकी सुरक्षा के लिए भी सबसे अधिक बलिदान सिख पंथ के अनुयायी ही देते आए हैं।

मातृशक्ति को सशक्त करने की परंपरा भी सिख पंथ ने दी

शाह ने कहा कि मातृ शक्ति को सशक्त करने की परंपरा सिख पंथ में माता खिवी के लंगर की सीख से वर्षों पहले शुरू हुई। इतिहास में भी ये दर्ज है कि सिख पंथ से निकली मातृशक्ति ने न केवल आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि देश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। सिख पंथ की इसी सीख को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राज्यों की विधानसभाओं और संसद में मातृशक्ति को 33 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए कानून बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

तुच्छ मामलों को लेकर कोर्ट की सहनशीलता की भी एक सीमा...

पीठ ने कहा कि चूंकि शपथ राज्यपाल ने दिलाई थी और बाद में सदस्यता ली थी इसलिए ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह याचिकाकर्ता के लिए प्रचार पाने का एक तुच्छ प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुच्छ मामलों को लेकर न्यायालयों की सहनशीलता की भी एक सीमा है। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिका में दावा किया गया था कि जस्टिस उपाध्याय को दिलाई गई शपथ दोषपूर्ण थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, हमारे एक-एक मिनट की कीमत है। इसका वित्त पर प्रभाव पड़ता है। इस मामले की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक लाख रुपये जमा करने की पूर्व शर्त थी।

क्या थी वकील की दलील

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि चीफ जस्टिस ने शपथ लेते समय अपना नाम लेने से पहले 'आई' (मैं) शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लंघन है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रतिनिधियों को शपथ में आमंत्रित नहीं किया गया था।

पीठ की टिप्पणी

पीठ ने कहा कि चूंकि शपथ राज्यपाल ने दिलाई थी और बाद में सदस्यता ली थी इसलिए ऐसी आपत्तियां नहीं उठाई जा सकतीं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह याचिकाकर्ता के लिए प्रचार पाने का एक तुच्छ प्रयास है। यह अधिक गंभीर मामलों से अदालत का ध्यान भटकाता है और न्यायिक मैनपावर और संसाधनों को नष्ट करता है। ऐसी याचिकाओं को खारिज करने का समय आ गया है और इसलिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है।

ड्रोन पर 5 परीक्षणों में कामयाबी हासिल करने वाला भारत पहला देश

हर अध्ययन के बाद तैयार हो रही एसओपी

भारत में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल कर साल 2020 व 2021 में कोरोना टीके और दवाओं को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाया गया। इसमें सफलता के बाद सरकार ने चार और नए कामों के लिए ड्रोन परीक्षण का फैसला लिया। इसके तहत वैज्ञानिकों की टीम भी गठित हुई। भारत ने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए प्राथमिक अस्पतालों तक रक्त पहुंचाने व टीबी की इलाज अवधि को कम करने में कामयाबी हासिल की है। अब तक पांच परीक्षणों में कामयाबी हासिल करने वाला यह दुनिया का इकलौता देश है।

ग्रामीण, खासकर दुर्गम स्थल के निवासियों में टीबी की इलाज अवधि को कम करने में ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई है। यह दो पायलट प्रोजेक्ट सरकार की उस चार लेयर नीति का हिस्सा हैं जिसे ड्रोन परीक्षण के लिए कुछ ही समय पहले अनुमति दी गई। अब केंद्र की ओर से राज्यों के मार्गदर्शन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

अप्रैल माह में शुरू हुआ ट्रायल

जानकारी के अनुसार, भारत में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल कर साल 2020 व 2021 में कोरोना टीके और दवाओं को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाया गया। इसमें सफलता के बाद सरकार ने चार और नए कामों के लिए ड्रोन परीक्षण का फैसला लिया। इसके तहत वैज्ञानिकों की टीम भी गठित हुई। इनका पहला कार्य एक से दूसरे अस्पताल तक रक्त पहुंचाना था। रक्त में प्लेटलेट्स सहित सभी घटकों को नुकसान पहुंचाए बगैर ड्रोन से आपूर्ति के लिए दिल्ली और नोएडा को चुना गया। इस साल अप्रैल माह में ट्रायल शुरू हुआ जिसके परिणाम हाल ही में जारी हुए हैं। दूसरा परीक्षण तेलंगाना के यद्रादी इलाके में इसी साल शुरू हुआ। यहां के दूरदराज गांव से टीबी संदिग्ध मरीज का सैंपल लेकर बड़े अस्पताल में जांच के लिए ड्रोन से भेजा गया। एक ही दिन में सैंपल जाने के बाद शाम तक रोगी को रिपोर्ट आई और तीन माह की दवाएं भी ड्रोन से प्राप्त हुईं। तीन से चार महीने तक रोज यह अभ्यास किया गया। इसके आंकड़े वैज्ञानिकों तक पहुंच गए हैं। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुमित अग्रवाल ने बताया, 'भारत में ऐसे कई गांव हैं, जहां से जिले तक पहुंचने में लोगों को 20 से 30 घंटे तक का समय लगता है। इसी समय को कम करने, आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, मरीज की तुरंत जांच व इलाज शुरू करने के लिए ड्रोन की एक बड़ी भूमिका सामने आई है।'

आज केलांग रवाना होंगे वैज्ञानिक

जानकारी मिली है कि ड्रोन के बाकी दो परीक्षण के लिए दिल्ली से वैज्ञानिकों का दल शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग के लिए रवाना होगा। लाहौल स्पीति जिला स्थित सात से आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और केलांग जिला अस्पताल के बीच ड्रोन परीक्षण होगा। यह पूरा इलाका दुर्गम है जहां हवा का दबाव भी कम रहता है।

अब तक सिर्फ परीक्षण ही क्यों?

इस सवाल पर डॉ. सुमित अग्रवाल ने कहा कि ड्रोन पूरी दुनिया के लिए नया है। कई देश इसका दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन भारत मानवता और हर किसी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए पहले वैज्ञानिक तथ्य, अध्ययन और दिशा निर्देश जरूरी हैं। अलग अलग विषयों के साथ अब तक कई अध्ययन हो चुके हैं। जल्द ही बाकी परिणाम भी हमारे हाथ में होंगे इसके बाद भारत अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग आगे बढ़ा सकता है।

ड्रोन ने 20 हजार खुराक पहुंचाईं

ड्रोन ने पायलट परीक्षण में 2020-2021 में 20 हजार टीकों की खुराक दुर्गम स्थानों तक पहुंचाई। अब तक यह आंकड़े सार्वजनिक नहीं थे लेकिन वैज्ञानिकों का अध्ययन जारी हुआ है। इसमें ड्रोन को दुर्गम स्थानों पर किन-किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी है।

टीबी पर सबसे अनूठा प्रयोग

डॉ. अग्रवाल बताते हैं कि टीबी और ड्रोन को लेकर यह अनूठा प्रयोग है। एक गांव में आशा कर्मचारी किसी संदिग्ध को टीबी की जांच कराने की सलाह देती है तो अमूमन बड़े शहर तक जाने और जांच कराने में कम से कम तीन-चार दिन का समय लगता है। साथ ही उसका खर्च भी बढ़ता है। इसके अलावा, जांच कराने के लिए वह अपना मन बनाने में भी समय लेता है। तीन से चार महीने तक चलने वाले इस ड्रोन परीक्षण में इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखा गया और अब हमारे पास प्रारंभिक आंकड़े हैं। इनका हमारी टीम अध्ययन कर रही है। फिलहाल इतना काफी है कि दुर्गम स्थल या ग्रामीणों में ड्रोन के जरिए टीबी की इलाज अवधि को कम करने में कामयाबी मिली है।

नितिन गडकरी ने लोस चुनाव को लेकर कही बड़ी बात

वोट देना है तो दो, माल-पानी कुछ नहीं मिलेगा

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके लोकसभा क्षेत्र नागपुर में उनके कोई बैनर या पोस्टर नहीं होंगे और लोगों को चाय नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे वे देंगे, जिन्हें नहीं देना होगा नहीं देंगे। महाराष्ट्र के वाशिम में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान, गडकरी ने कहा कि वह रिश्वत नहीं लेंगे और किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव के लिए मैंने तय किया है कि कोई भी बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा. लोगों को चाय नहीं दी जाएगी. जिन्हें वोट देना है वे वोट देंगे और जिन्हें नहीं देना है वे नहीं देंगे। न तो रिश्वत लूंगा और न ही किसी को रिश्वत दूंगा। लेकिन, मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर सकूंगा। इससे पहले जुलाई में, गडकरी ने एक निजी किस्सा साझा किया था और कहा था कि उन्होंने एक बार चुनाव के दौरान मतदाताओं को मटन उपलब्ध कराया था, लेकिन फिर भी वह हार गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं के प्रति विश्वास और प्यार पैदा करके चुनाव जीता जा सकता है।

उन्होंने नागपुर में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (एमएसटीसी) के समारोह में बोलते हुए यह टिप्पणी की। गडकरी ने कहा कि मतदाता बहुत होशियार हैं और उन्हें हर उम्मीदवार से चुनावी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सही है। लोग अक्सर पोस्टर लगाकर और चुनावी ख़ैरात देकर चुनाव जीतते हैं। हालाँकि, मैं ऐसी रणनीतियों में विश्वास नहीं करता। मैंने एक बार एक प्रयोग किया और मतदाताओं को एक किलोग्राम साओजी मटन उपलब्ध कराया।

राजनीतिक पार्टियों के साथ मीडिया पर भी चुनाव आयोग की नजर...

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राजस्थान, तेलांगना और मिजोरम में आचार संहिता लग गई है। इन राज्यों की गतिविधियों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी। वहीं मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। इन पांच राज्यों में कौन सी खबर और कैसी खबर निकल रही है, इसको लेकर आयोग भी मीडिया संस्थानों से नियमों का अनुपालन करने को कहा है। वरना, कार्रवाई की जा सकती है।

कुछ साल पहले से ही आयोग इस पर पैनी नजर रखता है। बीते चुनावों के दौरान कई नामचीन संस्थाओं को आयोग के सवालों का जवाब देना पड़ा है और पत्रकार बिरादरी में उसकी किरकिरी भी हुई है। बीते दशक से पारंपरिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी आयोग की निगहबानी होती है। यदि किसी खबर के माध्यम से किसी दल अथवा किसी प्रत्याशी विशेष का चुनाव का प्रचार किया जाता है, तो ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले नियमों के तहत रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में पूर्व में ही कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं।बीते वर्षों में केंद्रीय चुनाव आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिस पर किए

जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए और तो और, राजनीतिक दलों से भी आयोग की ओर से कहा गया है कि बगैर अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए न करें। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर न केवल आचार संहिता लागू रहेगी, बल्कि वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री इसके अधीन रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब विकिपीडिया और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी देगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी

टीवी पर ज्यादा समाचार न देखें, बढ़ जाएगा तनाव...

इस समय पूरी दुनिया भर में इजरायल-हमास के बीच चल रहा युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग युद्ध की स्थिति और इस पर ताजा सूचना के लिए बार-बार टीवी या सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। टीवी-सोशल मीडिया पर कई बार गंभीर दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिससे लोगों में तनाव बढ़ रहा है।

इजरायल-हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लोग टीवी या सोशल मीडिया पर ज्यादा समाचार न देखें। इससे कुछ लोगों में तनाव बढ़ सकता है जिससे उन्हें कई समस्याएं हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लेने, स्वास्थ्यप्रद भोजन करने, प्रियजनों के संपर्क में रहने और प्रतिदिन व्यायाम करने की सलाह भी दी है।

दरअसल, इस समय पूरी दुनिया भर में इजरायल-हमास के बीच चल रहा युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग युद्ध की स्थिति और इस पर ताजा सूचना के लिए बार-बार टीवी या सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। टीवी-सोशल मीडिया पर कई बार गंभीर दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिससे लोगों में तनाव बढ़ रहा है। इससे कुछ लोगों में समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। विशेषकर युद्ध प्रभावित क्षेत्र, या प्रभावित समुदायों के लोग बार-बार युद्ध की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनमें तनाव बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे बचने की सलाह दी है।

क्या हो सकता है असर

बार-बार भूकंप के समाचार सुनने से लोगों को यह मतिभ्रम होने लगता है कि दीवार, पंखे या भूमि हिल रही है। इसी प्रकार युद्ध के ज्यादा समाचार सुनने से लोगों में उसी के चित्र बार-बार याद रह सकते हैं जो उनमें डर, भय या अतिसंवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यह व्यवहार सामान्य नहीं होता और इसका असर कुछ समय से लेकर लंबे समय तक दिखाई पड़ सकता है। लोगों को गंभीर मनोरोग से लेकर सामान्य नकारात्मक वैचारिक विकार हो सकता है।

विशेषज्ञ ने बताया

इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकिएट्रिस्ट के चेयरमैन डॉ. मृगेश वैष्णव ने अमर उजाला से कहा कि यह बात सही है कि युद्ध के बहुत ज्यादा समाचार देखने-सुनने से लोगों में तनाव बढ़ सकता है। यदि यह तनाव का स्तर लगातार ज्यादा रहे तो इसका असर लोगों के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। इसलिए केवल जानकारी रखने तक के लिए समाचार देखना चाहिए। बार-बार उसे देखते रहने से मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। डॉ. मृगेश वैष्णव ने कहा कि मस्तिष्क के सीखने और उसे याद रखने का एक पैटर्न होता है। हम जो भी देखते-सुनते हैं, उसका 90 प्रतिशत हिस्सा एक दिन में ही भूल जाते हैं, लेकिन यदि एक ही चीज को लगातार बार-बार सुनें तो उसे याद रखने की समय सीमा बढ़ती चली जाती है। जब बीमार लोग, संवेदनशील लोग या अन्य लोग भी युद्ध के समाचार सुनते हैं तो इससे उनके मस्तिष्क पर नकारात्मक भावनात्मक असर पड़ता है। लेकिन यदि यही समाचार उन्हें लगातार सुनना पड़े तो इसका उनमें नकारात्मक असर दिखाई पड़ सकता है।

मीडिया बरते सावधानी

मीडिया चैनलों को चाहिए कि वे समाचार प्रकाशित करें, लेकिन अपनी दर्शक क्षमता बढ़ाने के लिए इसे महिमामंडित न करें। लोगों के घावों, शवों के ज्यादा वीभत्स दृश्य दिखाने से भी बचना चाहिए। सूचना देते समय डराने की नहीं, समझाने और गंभीरतापूर्वक किसी बात को समझने वाली शैली अपनाई जानी चाहिए।

बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते वाले आदेश पर पुनर्विचार को लेकर फैसला सुरक्षित...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समझौते से जुड़े एक मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने पुनर्विचार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर दोबारा विचार की अपील की गई है। अब मध्यस्थता से जुड़े अहम मामले पर सात जजों की पीठ को फैसला सुनाना है। अदालत के सामने सवाल है कि क्या ऐसे समझौते जिसमें मुहर नहीं लगे हैं? उन्हें भी कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है। कोर्ट को अपने आदेश की शुद्धता पर दोबारा विचार करना है।

मध्यस्थता समझौते पर पांच जजों की पीठ का फैसला

गुरुवार को शीर्ष अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौतों पर आदेश की शुद्धता पर पुनर्विचार मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले में पारित आदेश में कहा था कि बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौते कानून में लागू नहीं किए जा सकते। पुनर्विचार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखने वाली मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने डेरियस खंबाटा और श्याम दीवान सहित विभिन्न वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं।

मध्यस्थता के मकसद पर सीजेआई की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में खंबाटा ने कहा कि स्टांप या स्टांप की कमी एक दोष है जिसका इलाज संभव है। इससे ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए जहां पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते का उद्देश्य विफल हो जाए। दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजने का पूरा उद्देश्य 'अधूरा है और उद्देश्य विफल हो गया है।'

सात जजों की पीठ में कौन शामिल हैं? : पीठ ने कहा, 'अगर मध्यस्थता समझौतों में खामियां ठीक होने की संभावना है तो आप इसे कैसे खारिज कर सकते हैं?' बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

25 अप्रैल का आदेश, अब पुनर्विचार पर फैसला सुरक्षित : इससे पहले 26 सितंबर को फैसले की शुद्धता पर पुनर्विचार करने का मुद्दा सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने विगत 25 अप्रैल को आदेश पारित किया था। इसी फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत पर जोर दिया गया था। अदालत ने अप्रैल के फैसले में कहा था कि एनएन ग्लोबल के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण के बड़े प्रभावों और परिणामों को ध्यान में रखा है। हमारा विचार है कि दृष्टिकोण की शुद्धता पर पुनर्विचार करने के लिए कार्यवाही को सात-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

संविधान पीठ ने आदेश में क्या कहा? : अप्रैल के फैसले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से आदेश पारित किया था। पीठ ने कहा था, एक ऐसा दस्तावेज जिस पर स्टांप शुल्क लगना चाहिए, वह मध्यस्थता खंड हो सकता है। हालांकि, जिस पर मुहर नहीं लगी है, ऐसे दस्तावेजों को अनुबंध नहीं कहा जा सकता। अनुबंध अधिनियम की धारा 2(एच) के अर्थ के तहत कानूनी रूप से भी ये दस्तावेज बाध्यकारी नहीं होंगे। अनुबंध अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत भी इसे लागू नहीं किया जा सकता।

दस्तावेजों का कानूनी अस्तित्व नहीं : अदालत के आदेश के अनुसार, 'कोई बिना मुहर वाला दस्तावेज, जब उस पर मुहर लगाना जरूरी हो, अनुबंध नहीं है।' कानूनी रूप से भी ऐसे दस्तावेजों को प्रभावी नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे दस्तावेजों का कानून की नजरों में भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।

अदालत ने माना-मामला बेहद पेचीदा, समाधान जरूरी

मामले से जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं को देखते हुए मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा, अदालत का मानना है कि इस मामले को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। देश भर में मध्यस्थों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जहां उन्हें बताया जा रहा है कि एक बिना मुहर वाला समझौता है। इस मुद्दे पर फिर से कानूनी लड़ाई का विकल्प खुला है। ऐसे में अदालत को इस पेचीदा मामले को हल करने की जरूरत है।'

फैसले में सुधार की दलील, वकील ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे एक वकील ने कहा कि पांच जजों की पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। यह निष्कर्ष निकालना कि अगर किसी समझौते पर मुहर नहीं लगी है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सही नहीं हो सकता।

ज्योतिरादित्य का उदय, हाशिए पर जाती यशोधरा-वसुंधरा...

मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू होने के बावजूद यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। यशोधरा वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में मंत्री हैं। वो पहले ही अपने अनिश्चित पोस्ट-कोविड स्वास्थ्य के कारण चुनावी राजनीति से बाहर हो चुकी हैं। हालाँकि, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले छह महीनों से वह नियमित रूप से सभी बैठकों में शामिल हुई हैं, दौरों पर गई हैं और नियमित काम कर रही हैं।

यशोधरा और वसुंधरा का राजनीतिक भविष्य

राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी बाधाओं को पार करने वाली वसुंधरा अब अस्तित्व की गंभीर लड़ाई में लगी हुई हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है और उनके कई समर्थक पार्टी टिकट हासिल करने में विफल रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा अपने आंतरिक विरोधियों से हिसाब चुकता करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भाजपा की संभावित भारी जीत, जैसा कि कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं और सर्वेक्षण एजेंसियों ने संकेत दिया है, उनकी संभावित राजनीतिक अप्रासंगिकता की ओर इशारा करती है। केंद्रीय मंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी ने राजस्थान के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका के लिए वसुंधरा

राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी बाधाओं को पार करने वाली वसुंधरा अब अस्तित्व की गंभीर लड़ाई में लगी हुई हैं।

के विकल्पों को प्रभावी रूप से सीमित कर दिया है। यशोधरा और वसुंधरा दोनों के करीबी सूत्र दुख और निराशा की भावना व्यक्त करते हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे, 'अम्मा साहेब', राजमाता विजयाराजे सिंधिया की बेटियों के रूप में वे भाजपा के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध रहीं। विजयाराजे 1980 में भाजपा की संस्थापक सदस्य थीं और भाजपा के पहले अवतार भारतीय जनसंघ की एक प्रतिष्ठित हस्ती थीं। एक बड़ी हस्ती होने के बावजूद, उन्होंने अपने छह दशक लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कोई मंत्री पद या गवर्नर पद की मांग नहीं की। राजमाता जनसंघ और भाजपा के लिए भी एक प्रमुख धन संग्रहकर्ता थीं।

राजमाता ने दी इंदिरा लहर को चुनौती

वास्तव में 1967 में मध्य प्रदेश विधानसभा में राजमाता के प्रवेश ने घटनाओं के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ का मार्ग प्रशस्त किया जब 36 कांग्रेस विधायक विपक्षी खेमे में चले गए और राजमाता को मिश्रा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे का मास्टरमाइंड माना गया। मध्य भारत में पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी पार्टी संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) ने सरकार बनाई। हालाँकि, राजमाता ने मुख्यमंत्री का पद अस्वीकार कर दिया और अपने निर्णय के लिए कोई कारण नहीं बताया। 1980 के दशक में जब उनसे भाजपा का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। उनके नेतृत्व में जनसंघ ने 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा लहर को चुनौती दी, वह समय था जब कांग्रेस ने सदन में 352 सीटें हासिल कीं। जनसंघ ने ग्वालियर क्षेत्र में भिंड से राजमाता, गुना से उनके बेटे माधवराव और ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी तीन सीटें जीतीं। कांग्रेस की नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व में कट्टरता आ गई। इंदिरा ने एक कांग्रेस नेता को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के उन्मूलन के दौरान रूढ़िवादियों को एक महत्वपूर्ण झटका देकर असाधारण राजनीतिक कौशल और वास्तविक राजनीति की गहरी समझ का प्रदर्शन किया।

प्रिवी पर्स की समाप्ति

प्रिवी पर्स 1947 में भारत के साथ एकीकरण के समझौते के तहत रियासतों के 565 शाही परिवारों को किया गया भुगतान था। हैदराबाद के निज़ाम सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें प्रति वर्ष 80 मिलियन रुपये से अधिक की कर-मुक्त पेंशन मिलती थी। सिंधिया को प्रति वर्ष 25 लाख रुपये मिलते थे। पहली बार, सिंधिया को अन्य राजघरानों के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ा। राजमाता ने अपने संस्मरणों में स्थिति में अचानक हुए इस बदलाव के बारे में लिखा है।

मध्य प्रदेश की जनता को 'मामा' ने दिया धोखा

अब चाचा पर करें भरोसा- दिल्ली सीएम केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में एक 'मामा' हैं, जिन्होंने प्रदेश के भांजे-भांजियों को बहुत धोखा दिया है। लेकिन इस बार राज्य की जनता 'मामा' पर नहीं बल्कि अपने इस 'चाचा' पर भरोसा जताए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। आप पार्टी के सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए रविवार को सतना में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार पुरानी सरकारों के घोटालों और पुराने मंत्रियों द्वारा एकत्र किए गए पैसे निकलवाएंगे। सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य में एक 'मामा' हैं, जिन्होंने प्रदेश के भांजे-भांजियों को बहुत धोखा दिया है। लेकिन इस बार राज्य की जनता 'मामा' पर नहीं बल्कि अपने इस 'चाचा' पर भरोसा जताए।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता का मानना है कि आप पार्टी को कोई 50 सालों तक हरा नहीं सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता से अपील है कि आप पार्टी को एक बार यहां से भी मौका दो, जिसके बाद लोग कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो आप पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपका बेटा, भाई और चाचा आपके बीच आ गया है। इसलिए मुझ पर भरोसा जताना।

उन्होंने कहा कि आज वह राज्य में लोगों को गारंटी देने आए हैं। साथ ही जब से उनकी पार्टी ने गारंटी देनी शुरू की है। तब से बीजेपी भी गारंटी-गारंटी करने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा ने कहा कि कि वह लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन उनकी गारंटी झूठी है। चुनाव आने पर यह लोग एक-दूसरे को गाली देने लगते हैं। लेकिन हमारी पार्टी लोगों की समस्याओं के समझती है। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने इस सभा में गारंटियों की घोषणा की है।

बिजली

मध्यप्रदेश में लंबे-लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली महंगी है, जबकि दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली और पानी की सेवा उपलब्ध है। 300 यूनिट तक बिजली का बिल ज़ीरो आता है। वहीं राज्य में 24 घंटे बिजली सिर्फ आप पार्टी दे सकती है। इन 76 सालों में दोनों पार्टियों को देख लिया है। उनकी पार्टी गलत तरीकों से आए बिजली के बिल नवंबर तक माफ कर देंगे। दिसंबर में चुनाव होगा। वहीं 30 नवंबर तक बिजली के सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे और अगले साल से राज्य में 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जाएगी।

शिक्षा

सीएम केजरीवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश के 'मामा' ने यहां के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्ग कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में इतना काम किया है कि प्राइवेट स्कूलों के 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल में नाम लिखवा लिया है। यहां भी प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। लेकिन उनकी सरकार आने पर कच्चे टीचर्स को पक्का कर दिया जाएगा और सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार किया जाएगा।

स्वास्थ्य

सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की भी हालत खस्ता है। जबकि दिल्ली में टेस्ट और दवाइंया फ्री हैं। 20 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। छोटी-मोटी बीमारियों के लिए हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा दी गई है। ऐसे में मध्यप्रदेश के हर गांव में मोहल्ला क्लीनिक की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हर जिले के सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। जहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज होगा।

रोजगार

केजरीवाल ने कहा कि आप पार्टी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां देने का काम किया है। जबकि पंजाब में सिर्फ डेढ़ साल में 31 हजार सरकारी नौकरी दी गई और 3 लाख प्राइवेट नौकरियां दिए जाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। साथ ही जब तक रोजगार नहीं मिलता है, तब तक 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

एमपी में इस बार शिवराज की राह नहीं है आसान...

विकल्प बनने को तैयार भाजपा के ये दिग्गज

मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। किसी भी नेता का सीएम फेस के लिए नाम नहीं लिया गया है। वहीं दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अब सीएम फेस की लिस्ट में एक नहीं बल्कि 9 नाम सामने आ रहे हैं। जानिए इस लिस्ट में शिवराज किन नंबर पर हैं।

बीते 18 सालों से सत्ताधारी दल के रूप में मध्य प्रदेश पर काबिल भाजपा जहां एक बार फिर सत्ता पाने की कोशिश में जुटी है। वहीं इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होने के कारण चुनावी मैदान में उतारे गए शिवराज के समकक्ष कई दिग्गज मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं, जो सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री बनने की अपनी हसरत को बयान भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि भाजपा में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करने के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच लगभग यह स्पष्ट है कि इस बार सत्ता में वापसी के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर यह जिम्मेदारी मिल पाना मुश्किल है। इस बीच पार्टी द्वारा चुनावी मैदान में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और फगन सिंह कुलस्ते आदि शिवराज से भी ज्यादा वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के कारण इन तमाम नेताओं के बीच मुख्यमंत्री बनने की लालसा होना सामान्य है। यही कारण है कि इस बार अपनी हसरत को सार्वजनिक करने में ना तो कैलाश विजयवर्गी पीछे रहे और ना ही गोपाल भार्गव को कोई एतराज हुआ।इस बीच माना जा रहा है कि भाजपा के सत्ता में वापसी की स्थिति पर मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दो नहीं बल्कि भाजपा में ही आठ दिग्गज नेता हैं। हालांकि वर्तमान चुनावी सर्वेक्षण और एंटी इनकंबेंसी के फलस्वरूप कई नेता यह भी मान रहे हैं कि इस बार भाजपा के लिए सत्ता में आना बहुत मुश्किल होगा। जैसे आईए जानते हैं आखिर कौन सा प्रतिनिधि अपने किस रणनीति के तहत सीएम बनने की लालसा रखे हुए हैं।

नरेंद्र सिंह तोमरः तोमर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा फिलहाल में केंद्र में कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। तोमर का मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान से भी खास सामंजस्य रहा है। इसके अलावा पिछली बार भी तोमर का ही नाम मुख्यमंत्री को लेकर चला था, हालांकि इस तरह का फेरबदल संभव नहीं माना जा रहा है कि यदि भाजपा के लिए चुनाव में तमाम परिस्थितियां अनुकूल रही, तो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की सहमति से मैनेजमेंट में माहिर अनुभवी कहे जाने वाले तोमर बाजी मार सकते हैं। यही वजह है कि वह दिमनी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारने के बाद न केवल उनकी विधानसभा की जीत बल्कि मध्य प्रदेश की तमाम बहुमत वाली सीटों पर जीत की उम्मीद लिए हुए मुख्यमंत्री चुने जाने की दौड़ में खुद को सबसे आगे महसूस करते हैं।

वीडी शर्माः विष्णु दत्त शर्मा फिलहाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए हैं। स्वयंसेवक संघ से उनके करीबी और सामंजस्य के चलते हुए मुख्यमंत्री की दौड़ में लंबे समय से शामिल हैं।

कैलाश विजयवर्गीयः मैनेजमेंट में माहिर पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए हैं। हाल ही में महासचिव पद पर रहते हुए उन्हें इंदौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर इसे पार्टी के फैसले पर छोड़ने के बावजूद भी वे अपने मुख्यमंत्री पद के प्रति प्रेम को कई बार उजागर भी कर चुके हैं। इस बार क्योंकि वह फिर चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम बनने की उम्मीद उन्हें सर्वाधिक है।

ज्योतिरादित्य सिंधियाः सिंधिया भाजपा में एक फेस के रूप में स्थापित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 51 फीसदी ओबीसी आबादी के अलावा वे ओबीसी चेहरे के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं। कांग्रेस की सरकार में भी वह इसी उम्मीद के मद्देनजर पार्टी छोड़कर भाजपा में आए थे।

प्रहलाद पटेलः प्रहलाद पटेल का पूर्व में भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर नाम चला था, लेकिन पार्टी आला कमान ने इस तरह का फैसला नहीं लिया था। केंद्र में मंत्री और पुराने अनुभवी नेता होने के साथ प्रहलाद पटेल भी ओबीसी चेहरे के रूप में उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। जिसे लेकर वह भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लिए दौड़ में नजर आते हैं।

फगन सिंह कुलस्तेः फग्गन सिंह कुलस्ते भी आदिवासी चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर उम्मीद में है, क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग भी उठ चुकी है।

राजनीतिक बाज़ार गर्म

मुद्दे : इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे यह एक बड़ा विषय है। ऐसे ही पांच बड़े मुद्दे हम आपको बताने जा रहे हैं जिन पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। हर मंच पर इन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है। जनता का ध्यान इन्हीं पर केंद्रित करने का प्रयास राजनीतिक दल कर रहे हैं। इनमें, ओबीसी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लाडली बहना नारी सम्मान और सनातन शामिल हैं। चुनावों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भाजपा ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी (सीहोर) से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चौथी लिस्ट में तकरीबन ज्यादातर विधायकों और मंत्रियों को टिकट दिया गया है। अब तक भाजपा ने 136 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी 39 तो बसपा अब तक 42 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस इस दौड़ में पिछड़ गई है पार्टी की ओर से अब तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बिगुल बज चुका है। मध्यप्रदेश समेत पांच राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होंगे, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार 229 है। जिसमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 है। जबकि महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। वहीं, थर्ड जेंडर 1373 है।

जबकि 75 हजार 304 पोस्टल बैलेट से वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता जिनकी उम्र 18-19 वर्ष की है उनकी संख्या 22 लाख 36 हजार 564 है जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वर्ष 1957 से विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को देखने पर पता चलता है कि हर चुनाव में मतदाता संख्या में वृद्धि होती रही है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में पहले चुनाव हुए थे, उस वक्त प्रदेश में 1 करोड़ 38 लाख 71 हजार 727 मतदाता थे। मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश की 148 सीटें सामान्य, 35 सीटें अनुसूचित जाति, 47 सीटें अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

एक चरण में चुनाव के मायने

मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव को राजनीतिक दलों को फायदे नुकसान के हिसाब से देखें तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दो महीने पूर्व ही चुनावी मोड पर आकर सरकारी संसाधनों के माध्यम से अपनी विभिन्न योजनाओं का हर स्थान पर जाकर प्रचार कर चुकी है। सरकारी खर्चों पर मुख्यमंत्री की विभिन्न सभाएं , जैसे लाडली बहना सम्मेलन, किसान सम्मेलन जनजातीय सम्मेलन सरकारी नीतियों को बताने के अलावा पॉलिटिकल माइलेज लेने के भी जरिये थे। इसके अलावा उन्होंने अपने 136 उम्मीदवार तय कर उन्हें मैदान में भेज दिया है। इसके मायने यह है कि वह चुनावी किताब के सिलेबस को एक बार पढ़ चुके हैं और अब रिवीजन बाकी है। कुल मिला कर एक चरण के चुनाव के हिसाब से उनकी तैयारी बेहतर मानी जा रही है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने न तो अपने उम्मीदवार तय किए हैं। न ही वह तुलनात्मक रूप से अपने नेताओं और कार्यक्रमों को जनता के बीच भेज पाई है। इसलिए उन्हें एक ही चरण में चुनाव होने की वजह से अत्यधिक मेहनत करना होगी। इसमें उम्मीदवार तय होने के बाद की खींचतान और मान मनौव्वल में जाने वाला समय और ऊर्जा भी शामिल है। कई चरण चरण में होने वाले चुनाव का शुरुआती चरण के प्रत्याशियों को नुकसान होता है। उन्हें दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले चुनाव प्रचार और तैयारियों का कम समय मिल पाता है।

उल्लेखनीय है की निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हमारे साथ अपने सुझाव और फीडबैक शेयर किए हैं, जिसमें हमने सभी का उत्तर भी दिया है। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर तंज भी कसा है। उन्होंने फ्री कल्चर पर बात करते हुए कहा कि 'लोकप्रिय घोषणाएं करना आसान है, लेकिन उन वादों का पूरा करना कठिन होता है। हालांकि ऐसी घोषणाओं को रोक पाना मुश्किल है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की घोषणाएं क्यों की जाती हैं? किसी स्टेट में कोई अनाउंसमेंट, किसी में कोई अनाउंसमेंट।। पता नहीं क्यों 5 साल से इनको याद नहीं आती और आखिरी के 15 दिन में सारी घोषणाएं की याद आती है। खैर ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है।'

सांची स्तूप पर जाने वाले मुख्यमंत्रियों को गंवानी पड़ी थी सत्ता

क्या सीएम शिवराज सिंह तोड़ पाएंगे यह मिथक..

मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची को लेकर एक अंधविश्वास है। माना जाता है कि सांची पहाड़ी पर जो भी सीएम जाता है, उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है। ऐसे में हाल ही में सीएम शिवराज इस पहाड़ी पर पहुंचे हैं। जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सीएम शिवराज इस मिथक को तोड़ पाएंगे या फिर वह भी सत्ता से हाथ गंवा बैठेंगे।

मध्य प्रदेश की कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया जाने से बचते हैं। राजनेताओं में इन जगहों को लेकर अंधविश्वास या मिथक रहता है। बता दें यह मिथक सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में भी देखने को मिलता था। बता दें कि नोएडा को लेकर राजनेताओं के बीच में यह अंधविश्वास था कि यदि प्रदेश यानी की यूपी के सीएम यहां का दौरा करेंगे तो वह फिर से सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन 29-30 सालों से चला आ रहे इस अंधविश्वास को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। ऐसा ही अंधविश्वास मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची को लेकर भी है।

सांची पहुंचे सीएम शिवराज

बता दें कि स्तूप को शांति का टापू भी कहा जाता है। शांति की तलाश में दुनिया भर से लोग इस जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति का संदेश देने वाले इस विश्व प्रसिद्ध स्थल का दौरा करने से राजनेता आनाकानी करते हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह अंधविश्वास है कि जब भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इस सांची स्तूप पर पहुंचता है, तो फिर उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। हालांकि हाल ही में सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान सांची सोलर सिटी का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने इस शहर का भी दौरा किया। सीएम चौहान सांची स्तूप की पहाड़ी पर भी गए थे।

इन मुख्यमंत्रियों ने गंवाई है कुर्सी

माना जाता है कि जब-जब कोई मुख्यमंत्री सांची स्तूप की पहाड़ी पर पहुंचा है, तो फिर उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। यह सिलसिला दिग्विजय सिंह के समय से शुरू हुई थी। बता दें कि तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सांची गए थे। जिसके बाद उनके हाथों से सत्ता हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद तत्कालीन सीएम बाबू लाल गौर भी अपने कार्यकाल के दौरान सांची पहुंचे थे। कुछ समय बाद ही उनको भी सत्ता गंवानी पड़ी। सांची की स्तूप पहाड़ी पर जाने के बाद उमा भारती को भी सत्ता गंवानी पड़ी थी।

ऐसे में पिछली बार जब सीएम शिवराज यहां आए थे, तो उनके हाथों से भी सत्ता की चाभी फिसल गई थी। लेकिन एक बार फिर सीएम शिवराज ने रिस्क लेते हुए सांची की पहाड़ी पर पहुंचे हैं। सांची जाते ही चर्चा गर्म हो गई है कि क्या सीएम शिवराज के सांची पहाड़ी जाने से फिर से उनकी सरकार पर संकट आएगा। या फिर इस बार सीएम शिवराज इस रिस्क को तोड़ पाएंगे। बता दें कि सांची क्षेत्र का अपने आप में एक प्रभाव है। सम्राट अशोक ने इसी जगह पर राजनीति छोड़ने का फैसला कर शांति की तलाश की थी। ऐसे में माना जाता है कि सांची शांति का संदेश देता है। सांची का यह प्रभाव हो सकता है कि सांची ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं को यह संदेश देता हो कि शांति की तरफ आओ।

लड़ाई कपड़े फाड़ने तक क्यों आई

छह बार के विधायक की सीट बदलने के क्या मायने?

केपी सिंह को टिकट मिलने के बाद भाजपा से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी नाराज हैं। उनके समर्थक नाराजगी जताने भोपाल तक पहुंच गए। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हुई उनकी नोकझोंक के एक वीडियो ने सियासी पारा काफी बढ़ा दिया है। बात कपड़े फटने तक आ गई।

मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कई जगह बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा शिवपुरी सीट को लेकर हो रही है। इस सीट पर पार्टी ने शिवपुरी जिले की ही पिछोर सीट से छह बार के विधायक केपी सिंह को टिकट दिया है। केपी सिंह को टिकट मिलने के बाद भाजपा से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी नाराज हैं। उनके समर्थक नाराजगी जताने भोपाल तक पहुंच गए। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हुई उनकी नोकझोंक के एक वीडियो ने सियासी पारा काफी बढ़ा दिया है। बात कपड़े फटने तक आ गई। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था? वीडियो सामने आने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच टकराव की खबरें क्यों आईं? शिवपुरी सीट को लेकर क्यों ववाल हो रहा है? पिछोर से छह बार जीतने वाले केपी सिंह शिवपुरी क्यों भेजे गए? शिवपुरी सीट का सियासी इतिहास कैसा है?

केपी सिंह को टिकट मिलने के बाद भाजपा से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी नाराज हैं। उनके समर्थक नाराजगी जताने भोपाल तक पहुंच गए। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हुई उनकी नोकझोंक के एक वीडियो ने सियासी पारा काफी बढ़ा दिया है। बात कपड़े फटने तक आ गई। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था? वीडियो सामने आने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच टकराव की खबरें क्यों आईं? शिवपुरी सीट को लेकर क्यों ववाल हो रहा है? पिछोर से छह बार जीतने वाले केपी सिंह शिवपुरी क्यों भेजे गए? शिवपुरी सीट का सियासी इतिहास कैसा है?

कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इसके बाद कई जगह विरोध और बगावत के मामले सामने आए। भाजपा से कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक मंगलवार को कमलनाथ के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पर कमलनाथ ने उनको दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कह दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा ने भी वीडियो को लेकर तंज कसा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं।'

कुछ देर बाद ही दोनों नेता वचन पत्र जारी करने एक मंच पर आए। वचन पत्र जारी करने से पहले कमलनाथ से कपड़े फाड़ने वाली बात को लेकर सवाल किया गया। कमलनाथ ने कहा, 'मैंने कहा था यदि आपकी बात वह नहीं मानें तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए।' इस पर दिग्विजय सिंह ने उनको टोकते हुए कहा, 'भैया, ए और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के, तो कपड़े किसके फटने चाहिए? बताओ।' दोनों के बीच इस संवाद को सुनकर लोगों ने भी ठहाके लगाए।

राजस्थान विस चुनाव में जाट और किसान निभाएंगे किंगमेकर की भूमिका

'गेमचेंजर' हैं ये 82 सीटें

राजस्थान में 82 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि इन सीटों पर जात और किसानों की संख्या ज्यादा है। भाजपा और कांग्रेस भी इन सीटों पर अपनी जीत पक्की करने के लिए जाट और किसानों का समर्थन हासिल कर उन्हें अपने पाले में करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

राजस्थान में 82 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि इन सीटों पर जात और किसानों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में किसान और जाट जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, वह चुनाव के फाइनल नतीजे में निर्णायक साबित होते हैं। जाट और किसान ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2013 में कांग्रेस से नाराज होकर जाटों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इससे बीजेपी को भारी जीत मिली और सत्ता पर काबिज हुई। वहीं साल 2018 में किसानों ने कांग्रेस पार्टी की ओर अपना समर्थन दिखाया तो अशोक गहलोत राज्य के सीएम बनें। ऐसे में इस बार यानी की साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जाट और किसानों की भूमिका फिर से किंगमेकर वाली है। वहीं भाजपा और कांग्रेस भी इन सीटों पर अपनी जीत पक्की करने के लिए जाट और किसानों का समर्थन हासिल कर उन्हें अपने पाले में करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

बीजेपी ने बनाई रणनीति

राजस्थान के चुनाव में बीजेपी ने जाटों और किसानों को फिर से पार्टी के पक्ष में लाने के लिए दांव चल दिया है। बीजेपी के तरफ से सतीश पूनियां को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया है। बता दें कि पुनिया जाट नेता हैं और वह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं सतीश पुनिया जाटों को बीजेपी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं किसानों के लिए भी बीजेपी ने कई अहम और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ताकि चुनाव में किसान बीजेपी की ओर अपना समर्थन रखें। राजस्थान की राजनीति के बारे में अच्छी समझ रखने वाले लोगों की मानें तो उनका कहना है कि भाजपा को साल 2018 के विधानसभा चुनावों में जाट की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में जाट समुदाय की नाराजगी के कारण बीजेपी ने सत्ता खो दी थी। पार्टी से जाट समुदाय दूर हो गया है, ऐसे में सतीश पुनिया जाट समुदाय और बीजेपी के बीच इस गैप को भरने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस ने बनाई रणनीति

वहीं विधानसभा चुनावों में जाटों और किसानों का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस भी कड़ी मेहनत कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जाट नेताओं को अहम पद भी दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों के लिए कई विकास योजानाओं की भी शुरूआत की है। बता दें कि जाट और किसानों के प्रभाव वाली सीटों पर कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा भी दौरे कर रहे हैं। राजस्थान के मारवाड़ जोन में जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही जिले आते हैं। इन जिलों में 42 विधानसभा सीटें हैं। यह सारी सीटें जाट और किसान समुदाय के प्रभाव वाली सीटें हैं। माना जाता है कि यहां पर जाट और किसान जिस भी पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं, उसी पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। इस साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनैतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा अपने लोगों की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है...

झोटवाड़ा विधानसभा सीट से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट कर उनके स्थान पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को मैदान में उतारा गया है। टिकट काटने पर राजपाल शेखावत के समर्थकों ने भाजपा मुख्यालय पर जाकर जमकर बवाल मचाया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में अगले विधानसभा चुनाव के टिकटों को लेकर अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही है। आगामी नवंबर महीने में देश के पांच प्रदेशों- मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा ने अभी तक मध्य प्रदेश में 136 सीटों पर छत्तीसगढ़ में 84 सीटों पर व राजस्थान में 41 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर कांग्रेस पर बढ़त तो बना ली है। मगर भाजपा की सूची में बहुत से मौजूदा विधायकों व पूर्व में प्रत्याशी रहे नेताओं के नाम काट दिए जाने से पार्टी में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

विभिन्न चुनावी एजेंसियों द्वारा किये गए सर्वे के आधार पर भाजपा ने पार्टी विरोधी लहर को रोकने के लिए बहुत-सी सीटों पर प्रत्याशियों में फेरबदल किया है। भाजपा द्वारा राजस्थान में 6 लोकसभा व एक राज्यसभा सदस्य को, मध्य प्रदेश में तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित सात लोकसभा सदस्यों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित चार सांसदों को चुनाव मैदान में उतर गया है। हालांकि भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों को उन्हीं सीटों पर मैदान में उतारा है जहां पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। मगर सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट देने से उस क्षेत्र में विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। कई क्षेत्रों में प्रत्याशी पिछले पांच साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वहां सांसदों को टिकट देने से उनमें नाराजगी व्याप्त हो रही है।

राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव करीबन 31232 वोटों से जीता था। उनका टिकट कटने से उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि मेरा टिकट काटकर मुगलों के सामने घुटने टेकने वालों को टिकट देना कहां का इंसाफ है। हालाँकि बाद में राजवी अपने बयान से पलट गए। दीया कुमारी अभी राजसमंद से सांसद हैं तथा 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं।

जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट कर उनके स्थान पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को मैदान में उतारा गया है। टिकट काटने पर राजपाल शेखावत के समर्थकों ने भाजपा मुख्यालय पर जाकर जमकर बवाल मचाया। राजपाल शेखावत कई बार विधायक तथा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार दो बार जयपुर ग्रामीण से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं।

अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से विधानसभा का टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे विकास चौधरी तो अपने टिकट काटने पर रोने लगे तथा कहा कि पैसों के बल पर टिकट दी गई है। हालांकि भागीरथ चौधरी 2003 व 2013 में किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। 2018 में उनका टिकट काट दिया गया था। फिर 2019 को उनको अजमेर से लोकसभा का टिकट दिया गया था और वह चुनाव जीत गए थे। झुंझुंनूं के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ को मंडावा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र कुमार मंडावा से चार चुनाव लड़ चुके हैं। जिसमें वह दो बार हारे व दो बार जीते थे। 2018 में उन्होंने भाजपा टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। मगर 2019 में उन्होंने सांसद बनने पर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।

जालौर से लगातार तीन बार के सांसद देवजी पटेल को सांचौर से वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने मैदान में उतारा गया है। सांचौर से भाजपा एक बार 2003 में ही जीत पाई थी। सांचौर से सांसद देवजी पटेल को टिकट मिलने से वंचित टिकट दावेदारों में आक्रोश है। वहां सांसद के काफिले को लोगों ने बीच रास्ते में रोका व काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया और काफिले के वाहनों पर पथराव किया जिससे दो से तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस उग्र प्रदर्शन से घिरे सांसद देवजी पटेल ने जैसे-तैसे अपनी जान बचायी। राजस्थान में भाजपा के हिन्दुवादी चेहरे अलवर सांसद महंत बालकनाथ को तिजारा से मैदान में उतारा गया हैं। वहां भाजपा के पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने कि घोषणा कर दी है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर सीट से प्रत्याशी बनाया। किरोड़ीलाल मीणा 5 बार विधायक, दो बार लोकसभा सदस्य व एक बार राज्यसभा सदस्य तथा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वह एक बार सवाई माधोपुर से विधायक भी रह चुके हैं। राजस्थान में भाजपा ने केन्द्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कि अध्यक्षता में एक कमेटी बनायीं है जो बागी प्रत्याशियों को समझाकर मनायेगी। इस कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। भाजपा के कई बड़े नेता अलग-अलग जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें समझा रहे हैं।

पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, वह लापता युवती प्रेमी संग लौटी तो थाने में करवा दी शादी

पुलिस जिस युवती की सरगर्मी से तलाश में जुटी थी वह मंगलवार रात स्वयं जा पहुंची। युवती को देख पहले तो पुलिसकर्मी चौंक गए। जैसे ही उसने प्रेमी संग जाना बताया पुलिसकर्मी शादी की तैयारियों में जुट गए। थाना परिसर में ही वरमाला पहनाकर दोनों ने शादी कर ली।

टीआइ राजेश साहू के मुताबिक, धर्मराज कालोनी निवासी 22 वर्षीय सिमरन 15 अक्टूबर को घरवालों को बताए बगैर चली गई थी। मां कोमल द्वारा थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। लड़की के साथ गलत न हो इस टेंशन में पुलिसवालों भी तलाश में लगे हुए थे। मंगलवार रात सिमरन प्रेमी जतीन तिवारी निवासी नगीन नगर के साथ थाने पहुंच गई।

सिमरन ने कहा कि वह जतीन से प्रेम करती है और उसके साथ ही रहेगी। सिमरन के स्वजन को पुलिस ने बुलाया तो पहले शादी से आनाकानी करने लगे। पुलिसवालों ने कहा, लड़की बालिग है। उस पर किसी चीज का दबाव नहीं बनाया जा सकता। जतीन के स्वजन भी शादी नहीं करना चाहते थे। पुलिसवालों के समझाने पर उन्हें भी मानना पड़ा। रात में पुलिसवालों ने शादी की तैयारी करवाई परिसर में बने मंदिर में दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर ली। टीआइ के मुताबिक, मंदिर परिसर में ही वर-वधु पक्ष के उन लोगों को बुलाया

गया था जो शादी के खिलाफ थे। दोनों पक्षों ने रजामंदी दी और स्वयं शादी में शामिल हुए।

प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीटा : भंवरकुआं पुलिस ने राजकुमार वर्मा की शिकायत पर सलमान पटेल और पत्नी प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज किया है। आलोक नगर मूसाखेड़ी निवासी राजकुमार का आरोप है कि पत्नी प्रियंका खंडवा रोड़ पर सलमान के साथ थी।उसने इसका विरोध किया तो प्रियंका और सलमान ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। रात में पुलिस ने दोनों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया।

कपड़े की फर्जी फर्म बनाकर गुजरात और मुंबई के कारोबारियों से ठगे ढाई करोड़

गुजरात और मुंबई के बड़े कपड़ा कारोबारियों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच ने चार आरोपितों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। मास्टर माइंड कोचिंग इंस्टिट्यूट संचालक है जो फर्जी फर्म बनाकर लोगों को चपत लगा रहा था। अपराध शाखा के डीसीपी निमिष अग्रवाल के मुताबिक, आरोपित अरविंद पांडे निवासी ग्रीन पार्क कालोनी हलधरु कामरेज सूरत (गुजरात), लक्ष्मीकांत शुक्ला निवासी रघुकुल नगर नवागम डिंडोली सूरत (गुजरात), देवी प्रसाद उपाध्याय निवासी बालाजी रेसीडेंसी डिंडोली सूरत (गुजरात) और चेतन जैन निवासी सीताश्री रेसीडेंसी एरोड्रम रोड़ इंदौर है। डीसीपी के मुताबिक, मामले में सिमु इंपेक्स प्रा.लि. के डायरेक्टर सुमीर किनरा और रघुवीर फेब्रिक के शुभम वैद्य, आदित्य सिंथेटिक्स द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी।

माल खरीदकर रातों रात दुकान बंद कर हुए फरार शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि उनसे डीके ट्रेडिंग कंपनी एवं बालाजी इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर्स ने धोखाधड़ी की है। आरोपितों ने इंदौर के सियागंज में दुकान खोली और गुजरात व मुंबई के व्यापारियों से कपड़ों का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में एजेंट के माध्यम से लेनदेन हुआ और साख स्थापित करने के उद्देश्य से वक्त

पर रुपये जमा करवाते गए। बाद में लाखों रुपयों का माल खरीदा और रातोंरात दुकाने बंद कर फरार हो गए।

पुलिस ने छात्र बनकर की रैकी : पुलिस ने आरोपितों के बैंक खातों और आधार कार्ड की जांच की तो पता चला सारे शासकीय दस्तावेज दुकानों के पतों पर अपडेट करवा लिए गए थे। बैंक खाते भी दुकान के पते पर थे, जो किराए से ली थी। पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल की लोकेशन निकाली और सूरत टीम भेजी। मुख्य आरोपित अरविंद पांडे निकला। वह कोचिंग क्लास चलाने लगा था। पुलिसकर्मियों ने छात्र बनकर उसकी रैकी की और शुक्रवार को छापा मारकर पकड़ लिया। अरविंद ने बताया की देवी प्रसाद उसका दोस्त है। वह 20 वर्षों से कपड़ों के व्यवसाय से जुड़ा था। उसके साथ मिलकर फर्जी फर्म खोलकर लोगों को ठगने की साजिश की थी।

भाजपा सांसद का दाव...

जयपुर के लॉकर में बंद हैं 500 करोड़ रुपये और 50 किलो सोना...

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, भाजपा नेता जयपुर में एमआई रोड के पास एक फर्म के कार्यालय में गए - जहां उन्होंने दावा किया कि लॉकर स्थित थे। जबकि मीना ने दावा किया कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें मामले की जांच के लिए फर्म तक पहुंचीं, दोनों एजेंसियों की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है।

बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि राजस्थान पेपर लीक मामले में जयपुर के 100 निजी लॉकरों में 500 करोड़ रुपये का काला धन और 50 किलो सोना रखा हुआ है। पुलिस से लॉकर खोलने की मांग करते हुए, मीना ने दावा किया कि कुल लॉकर में से 50 चालू थे, जबकि 10 कुछ सरकारी अधिकारियों के थे। वरिष्ठ भाजपा नेता के आरोप 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आए हैं। मीना ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ''सरकारी भर्ती पेपर लीक घोटाला, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग घोटाला और जल जीवन मिशन घोटाले से कमाया गया काला धन लॉकरों में है।''

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, भाजपा नेता जयपुर में एमआई रोड के पास एक फर्म के कार्यालय में गए - जहां उन्होंने दावा किया कि लॉकर स्थित थे। जबकि मीना ने दावा किया कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें मामले की जांच के लिए फर्म तक पहुंचीं, दोनों एजेंसियों की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता जयपुर में एक फर्म के ऑफिस के पास गए - जहां उन्होंने दावा किया कि लॉकर स्थित थे। जबकि मीना ने दावा किया कि एसोसिएटेड तक फर्मों की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और निदेशालय (ईडी) के रिकॉर्ड मामले की पुष्टि नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने मीणा को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सवाई माधोपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने यहां पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया के सामने दावा किया, ''लगभग 100 लॉकर हैं जिनमें लगभग 500 करोड़ रुपये और 50 किलो सोना है। मैं तब तक गेट पर बैठा रहूंगा जब तक पुलिस आकर लॉकर नहीं खोल देती।'' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि लॉकर किसके हैं। मीणा ने कहा, ''मैं नामों का खुलासा बाद में करूंगा क्योंकि अगर मैं अभी खुलासा करूंगा, तो राजनीतिक दबाव में लॉकर नहीं खोले जाएंगे।

प्रेस क्लब से मीणा ने मीडिया से उस भवन तक उनके साथ चलने को कहा जहां के लॉकरों में उनके दावे अनुसार काला धन रखा है। वह मीडिया के साथ उस भवन में गए जहां लॉकर हैं। उन्होंने कहा, ''जयपुर पुलिस को लॉकर खोलने चाहिए।

भारतीय संस्कृति का असर

श्राद्ध के दौरान दादा-दादी और नाना-नानी का जैसलमेर में किया तर्पण

जैसलमेर के टूर के दौरान उन्हें श्राद्ध के संबंध में जानकारी हासिल हुई। उन्होंने स्थानीय पंडित से श्रद्धा के बारे में पूछा और फिर अपने दादा-दादी और नाना नानी का श्राद्ध करने की इच्छा जताई। महिलाओं ने गड़ीसर झील पर सनातन रीति रिवाज के अनुसार दिवंगतों से आशीर्वाद मांगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भारत की विदेशी संस्कृति का असर विदेशियों पर गहरा होने लगा है। वृंदावन मथुरा में आमतौर पर विदेशी लोगों कृष्ण भक्ति में रंगीन नज़र आते हैं। वहीं अब जैसलमेर आने वाली विदेशी सैलानियों पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है।

कई विदेशी सैलानी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर इसे अपनाने लगे हैं। इसी का ताजा उदाहरण जैसलमेर में ही देखने को मिला है जब फ्रांस की 17 महिला टूरिस्ट ने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण भी किया। महिलाओं के इस ग्रुप में जैसलमेर के अष्टांग योग केंद्र में योग करने के बाद गड़ीसर झील में श्राद्ध तर्पण किया। बता दे कि फ्रांस से महिला पर्यटकों का यह दल बीते सात या आठ दिनों से जैसलमेर में घूम रहा है। इस दौरान महिलाओं का यह दल हिंदू संस्कृति से खासा प्रभावित हुआ। महिलाओं का कहना है कि बीते 3 वर्षों से वह लगातार योग से काफी प्रभावित है और फ्रांस में भी योग करती है। महिलाओं के मुताबिक योग करने से उनके जीवन में कई सकारात्मक सुधार आए हैं। इसी बीच जैसलमेर के टूर के दौरान उन्हें श्राद्ध के संबंध में जानकारी हासिल हुई। उन्होंने स्थानीय पंडित से श्रद्धा के बारे में पूछा और फिर अपने दादा-दादी और नाना नानी का श्राद्ध करने की इच्छा जताई। महिलाओं ने गड़ीसर झील पर सनातन रीति रिवाज के अनुसार दिवंगतों से आशीर्वाद मांगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रीति रिवाज जानने के बाद महिलाओं ने थी तर्पण किया। जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने श्राद्ध करने के बाद काफी भावुक महसूस किया हालांकि उनका मन भी शांत हो गया। बता दे की सभी महिलाओं ने सनातन धर्म के अनुसार ही मंत्र और रीति रिवाज के साथ पूरी तर्पण विधि को किया है।

नारी शक्ति वन्दन अभियान...

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। परन्तु तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल सकी।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 21 सितंबर, 2023 को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कहा कि दो दिन से अत्यंत महत्वपूर्ण इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा के एक-एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो स्पिरिट पैदा हुई है, ये स्पिरिट देश के जन-जन में एक नया आत्मकविश्वामस पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान, सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्ज्वल भविष्य् की गारंटी बनने वाली है।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले करने वाले सभी राज्यसभा सांसदों

उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। परन्तु तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल सकी। चूंकि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। इसलिए यह विधेयक आसानी से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से इसके राजनीतिकरण पर भीविराम लग गया। नि :संदेह इस वेधेयक के लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, और यह उनकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सुना जाना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक कदम है।

इससे पूर्व केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा में बोलते हुए उन अमित शाह ने कहा था कि 19 सितम्बर 2023 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने वाला बिल सदन में पेश हुआ। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत हिस्से वाली मातृशक्ति को सच्चे अर्थों में सम्मानित करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक एजेंडा हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण मान्यता का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की महान जनता ने 30 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री का पदभार सम्भालने के दिन से ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में सरकार की श्वास और प्राण बने हुए हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाएं, पुरुषों से भी अधिक सशक्त हैं और इस विधेयक से अब डिसिजन और पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ये बिल समाज व्यवस्था की त्रुटि को सुधारने, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने और उनका सम्मान करने के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आज ये एक ऐसा मौका है जब इस सदन को पूरे विश्व को एक संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी की 'वुमन लीड डिवेलप्मन्ट' की कल्पना को पूरा करने के लिए पूरा सदन एकमत है।

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाने के पहले की सरकारों द्वारा चार प्रयास हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहली बार 1996 में देवेगौड़ा सरकार लेकर आई, इसके बाद इसे सीमा मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति को दे दिया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी लेकिन फिर वो विधेयक कभी इस सदन तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 में ये विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने इसे सदन में पेश ही नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक बार फिर अटल जी की सरकार बिल लेकर आई लेकिन एक बार फिर इस पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार संशोधन विधेयक राज्य सभा में लेकर आई, जहां पारित होने के बाद ये विधेयक लोक सभा में आ ही नहीं सका।

उन्होंने पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सब एकत्रित होकर इस नई शुरुआत के माध्यम से आज सर्वानुमति से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रावधान के अनुसार संसद में चुनकर आने वाले सदस्यों की तीनों श्रेणियों– सामान्य (जिसमें ओबीसी शामिल हैं), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति– में मोदी सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस संविधान संशोधन की धारा 330 (ए) और धारा 332 (ए) के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही तीनों श्रेणियों में वर्टिकल आरक्षण देकर एक-तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वह नियुक्ति से होता है लेकिन क्वासी ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं।

उन्होंने कहा कि इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं और इसमें चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन एक-तिहाई सीटों को रिजर्व करना है, उन सीटों का चयन डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। ये कमीशन हर राज्य में जाकर, ओपन हियरिंग देकर एक पारदर्शी पद्धति से इसके लिए नीति निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन के गठन से किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, चुनाव के बाद जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और जल्द ही वह दिन आएगा जब इस सदन में एक-तिहाई महिला सांसद बैठकर देश के भाग्य को तय करेंगी।

यात्रियों की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला

त्योहारी सीजन में रेलवे विभाग चलाएगा 34 स्पेशल ट्रेनें...

त्योहारी सीजन से पहले उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत रेलवे यात्रियों की त्योहारी भीड़ को देखते हुए बुधवार से 34 विशेष ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। विशेष ट्रेनें 18 अक्तूबर से 11 दिसंबर के बीच 377 चक्कर लगाएंगी। इनमें से 351 यात्राएं देश के पूर्वी हिस्से की ओर और 26 यात्राएं उत्तरी क्षेत्र की ओर होंगी। उत्तरी महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कहा, इन 34 ट्रेनों के अलावा, मौजूदा 69 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे और कुल मिलाकर, उत्तर रेलवे त्योहारी सत्र के दौरान यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि को देखते हुए 5.5 लाख अतिरिक्त बर्थ और सीटें बनाएगा। मेरा मानना है कि अतिरिक्त व्यवस्थाएं बढ़ी हुई मांग का ख्याल रखेंगी। हालांकि, हम स्थिति पर नजर रखेंगे और अगर हमें लगता है कि और अधिक विशेष ट्रेनों की जरूरत है, तो हम निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे। फिलहाल, मैं मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। विशेष ट्रेनों की समयबद्धता के बारे पर चौधरी ने कहा कि वे यथासंभव आगमन और प्रस्थान के निर्धारित समय को बनाए रखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों के कारण समय की पाबंदी नहीं खोएंगे। ये अतिरिक्त ट्रेनें हमारे लिए अन्य ट्रेनों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं और मैं विशेष ट्रेनों से यात्रा करने की योजना बना रहे सभी यात्रियों को आश्वस्त करूंगा कि उनकी समय की पाबंदी बनाए रखी जाएगी। उत्तर रेलवे ने संभावित यात्रियों को अपने सोशल मीडिया हैंडल और पूछताछ कार्यालयों से विशेष ट्रेनों का विवरण प्राप्त करने की सलाह दी है।

भीड़भाड़ और भगदड़ से बचने की रेलवे की तैयारी : उत्तर रेलवे ने बुधवार को त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को भीड़भाड़ और भगदड़ जैसी

घटनाओं से बचने के लिए अपनी ट्रेनों के प्रस्थान से 15 से 20 मिनट पहले स्टेशनों पर पहुंचने की सलाह दी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि यदि लोग जल्दी आते हैं तो उनके इंतजार के लिए विशेष होल्डिंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे और इससे सीमित जगह वाले प्लेटफार्मों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए हम बड़ी संख्या में सुरक्षा और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करेंगे।

चौधरी ने कहा, अगर लोग सावधान और सतर्क नहीं रहे तो भगदड़ जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। भीड़भाड़ होने पर लोग प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर गिर सकते हैं। इसके अलावा, वे खुद के लिए और अन्य यात्रियों के लिए भी बहुत असुविधा पैदा कर सकते हैं। बता दें 2010 में त्योहारी सीजन के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में दो लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे।

राष्ट्रपति मुर्मू के पैतृक जिले के लिए पहली यात्री ट्रेन की मंजूरी, रेल मंत्री ने दी जानकारी...

रेलवे ने राष्ट्रपति मुर्मू के पैतृक स्थान ओडिशा के लिए पहली यात्री ट्रेन को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक स्थान रायरंगपुर और मयूरभंज जिले के बादामपहाड़ को अब मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी। रेलवे ने राष्ट्रपति मुर्मू के पैतृक स्थान ओडिशा के लिए पहली यात्री ट्रेन को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले को उन चार जोड़ी ट्रेनों में से तीन मिल गईं जिन्हें हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में मंजूरी दी थी। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

ने ईसीओआर द्वारा जारी एक बयान में कहा, यह पहली बार है कि टाटा-बादामपहाड़ मार्ग पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक स्थान रायरंगपुर और मयूरभंज जिले के बादामपहाड़ को अब मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी।

रेल मंत्री अश्विनी बोले

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी। उन्होंने कहा, नई ट्रेन स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, आदिवासी क्षेत्र के विकास में मदद करेगी और आकांक्षी जिलों को अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी।

संपत्ति जब्त करने के अधिकार की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट...

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि 2022 का फैसला बहुत विचार-विमर्श के बाद दिया गया था और वर्तमान याचिकाओं के समूह में दिए गए सभी तर्क तब दर्ज किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के अधिकार की समीक्षा करेगा। पिछले साल शीर्ष अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में ईडी को मिले इस अधिकार को बरकरार रखा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ ने पिछले साल के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि 2022 का फैसला बहुत विचार-विमर्श के बाद दिया गया था और वर्तमान याचिकाओं के समूह में दिए गए सभी तर्क तब दर्ज किए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या तीन न्यायाधीशों की यह पीठ किसी अन्य समन्वय पीठ के फैसले की अपील पर सुनवाई कर सकती है। मेहता ने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति कल यह याचिका लेकर आ सकता है कि वह समलैंगिक विवाह मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से सहमत नहीं है और संदर्भ(रेफरेंस) या सुनवाई की मांग कर सकता है।

एफएटीएफ के मूल्यांकन तक इंतजार का अनुरोध

मेहता ने कहा कि पीएमएलए एक अकेला अपराध नहीं है और अन्य कानूनों के विपरीत, पीएमएलए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विधायिका की ओर से तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि हर सदस्य देश ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी कानून तैयार कर लिए हैं। मेहता ने अदालत से एफएटीएफ द्वारा आपसी मूल्यांकन खत्म होने तक इंतजार करने को कहा।

पीएमएलए संविधान के अनुरूप नहीं : कपिल सिब्बल

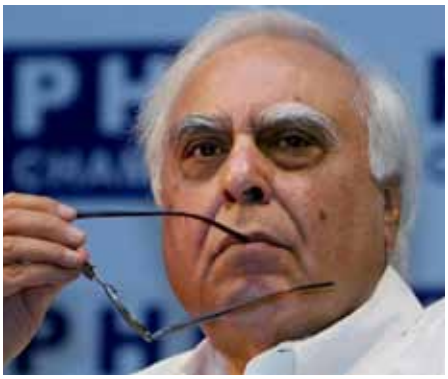

याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत ने कहा था कि पीएमएलए कोई दंडात्मक कानून नहीं है और यह उनकी पहली समस्या है। सिब्बल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किसी को दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है लेकिन अदालत का कहना है कि यह एक नियामक कानून है। सिब्बल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को पीएमएलए के तहत समन किया जाता है तो उसे नहीं पता होता है कि उसे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुरूप नहीं है। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की है।

2017 में कोर्ट ने धारा 45(1) को असांविधानिक ठहराया था

गौरतलब है कि नवंबर 2017 में, जस्टिस (सेवानिवृत्त) आर एफ नरीमन और जस्टिस कौल की पीठ ने पीएमएलए की धारा 45(1) को असंवैधानिक ठहराया था क्योंकि यह एक आरोपी को जमानत देने के लिए दो और शर्तें लगाती है। अदालत ने कहा था कि यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। वहीं विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 27 जुलाई, 2022 के फैसले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इसे खारिज कर दिया था।

ऐसे तो मुकदमेबाजी का अंत नहीं होगा

पीठ ने कहा कि अदालत प्रथम दृष्टया इस दलील से सहमत नहीं है और मामले से निपटेगी। मेहता ने कहा कि यह पीठ ऐसी कार्यवाहियों में इस पर दोबारा विचार नहीं कर सकती, अन्यथा मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा। पीठ ने मेहता से कहा कि प्रथम दृष्टया उनका विचार है कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ इससे निपट सकती है और इसमें कोई रोक नहीं हो सकती है। पीठ ने पूछा कि क्या यह पत्थर पर लिखा है कि एक पीठ दूसरी पीठ के फैसले पर गौर नहीं कर सकती है। पीठ ने कहा कि अदालत यह नहीं कह सकती कि वह कभी भी फैसले पर दोबारा विचार नहीं कर सकती।

हाई कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी प्रेमी जोड़े की याचिका

टाइम पास होते हैं... लिव-इन रिलेशनशिप

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की दो-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले एक अंतर-धार्मिक लिव-इन जोड़े द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव-इन रिश्ते बिना किसी स्थिरता या ईमानदारी के मोह के समान हैं। यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कम उम्र और साथ रहने में बिताए गए समय पर सवाल उठाया कि क्या यह सावधानीपूर्वक विचार किया गया निर्णय था। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की दो-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में दो महीने की अवधि में हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह जोड़ा एक-दूसरे के साथ रहेगा। इस प्रकार के अस्थायी संबंधों पर गंभीरता से विचार करने में सक्षम। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह

बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। अदालत ने आगे टिप्पणी की कि लिव-इन रिश्ते अस्थायी और नाजुक होते हैं और टाइमपास में बदल जाते हैं।

पीठ ने कहा कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। यह हर जोड़े को कठिन और कठिन वास्तविकताओं की ज़मीन पर परखता है। हमारा अनुभव बताता है कि इस प्रकार के रिश्ते अक्सर टाइमपास, अस्थायी और नाजुक होते हैं और इस तरह, हम जांच के चरण के दौरान याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा देने से बच रहे हैं। दंपति ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण, अपहरण या शादी के लिए मजबूर करने वाली महिला को प्रेरित करना) के तहत महिला की चाची द्वारा पुरुष के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

पाकिस्तान में एक और हिंदू लड़की का जबरन करा दिया गया निकाह, कोर्ट ने भी नहीं सुनी पीड़िता की फरियाद

रजीता का दो महीने पहले अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह अपने अपहरणकर्ता आशिक अहमदानी के चंगुल से भागने में सफल रही, जैसा कि पाकिस्तानी गैर-लाभकारी समाचार संगठन द राइज न्यूज ने 15 अक्टूबर को उसके कैद से भागने के दो दिन बाद रिपोर्ट किया था।

रजीता मेघवार कोल्ही खुद को फर्श पर गिरा देती है, रोती है और गुहार लगाती है कि वह अपने माता-पिता के साथ फिर से मिलना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की न्याय प्रणाली उसकी बात अनसुनी कर देती है और आंखें मूंद लेती है। रजीता पाकिस्तान की एक दलित हिंदू महिला है और वह अल्पसंख्यक समुदायों की उन हजारों महिलाओं में से एक है जिनका हर साल अपहरण कर लिया जाता था, उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाता था और उनसे शादी कर ली जाती थी। रजीता का दो महीने पहले अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह अपने अपहरणकर्ता आशिक अहमदानी के चंगुल से भागने में सफल रही, जैसा कि पाकिस्तानी गैर-लाभकारी

समाचार संगठन द राइज न्यूज ने 15 अक्टूबर को उसके कैद से भागने के दो दिन बाद रिपोर्ट किया था।

द राइज़ न्यूज़ ने रजीता कोल्ही का एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध एक व्यक्ति से शादी करने और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। पोस्ट में कहा गया कि उसे बताया गया कि अगर उसने उनकी मांगें नहीं मानी तो उसके माता-पिता को मार दिया जाएगा। वीडियो पर रजीता ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ फिर से मिलना चाहती थी लेकिन इसके बजाय उसे महिला आश्रय में भेज दिया गया। लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला के मामले में कोर्ट के रुख पर सवाल उठाए। यह ध्यान देने योग्य है कि मीरपुर खास (सिंध प्रांत का शहर) की इसी अदालत ने पहले एक मुस्लिम लड़की को उसके माता-पिता से मिलाने की इजाजत दी थी, जब उसके माता-पिता ने कहा था कि वह उनके साथ रहना चाहती है। अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ता शिव काछी ने कहा कि एक हिंदू लड़की रजीता के मामले में उसे एक सुरक्षित घर में भेज दिया गया था। दो दिन पहले, रजीता दो महीने तक अपहरण के बाद बाहर आई और एक वीडियो में एक बयान दिया, जिसमें उसने अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की।

प्रत्याशी घोषित... अब रूठों को मना कर डैमेज कंट्रोल का दौर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के इस बार के चुनाव कांटे के मुकाबले के हैं। सरकार किसी भी दल की बन सकती है और यही कारण है कि तमाम दावेदार चुनाव मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। जिन नेताओं को राजनीतिक दल टिकट नहीं दे रहे हैं वे बगावत कर सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। छोटे दलों की तरफ राजनेताओं का रुझान इसलिए भी है कि अगर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति बनती है, तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी।

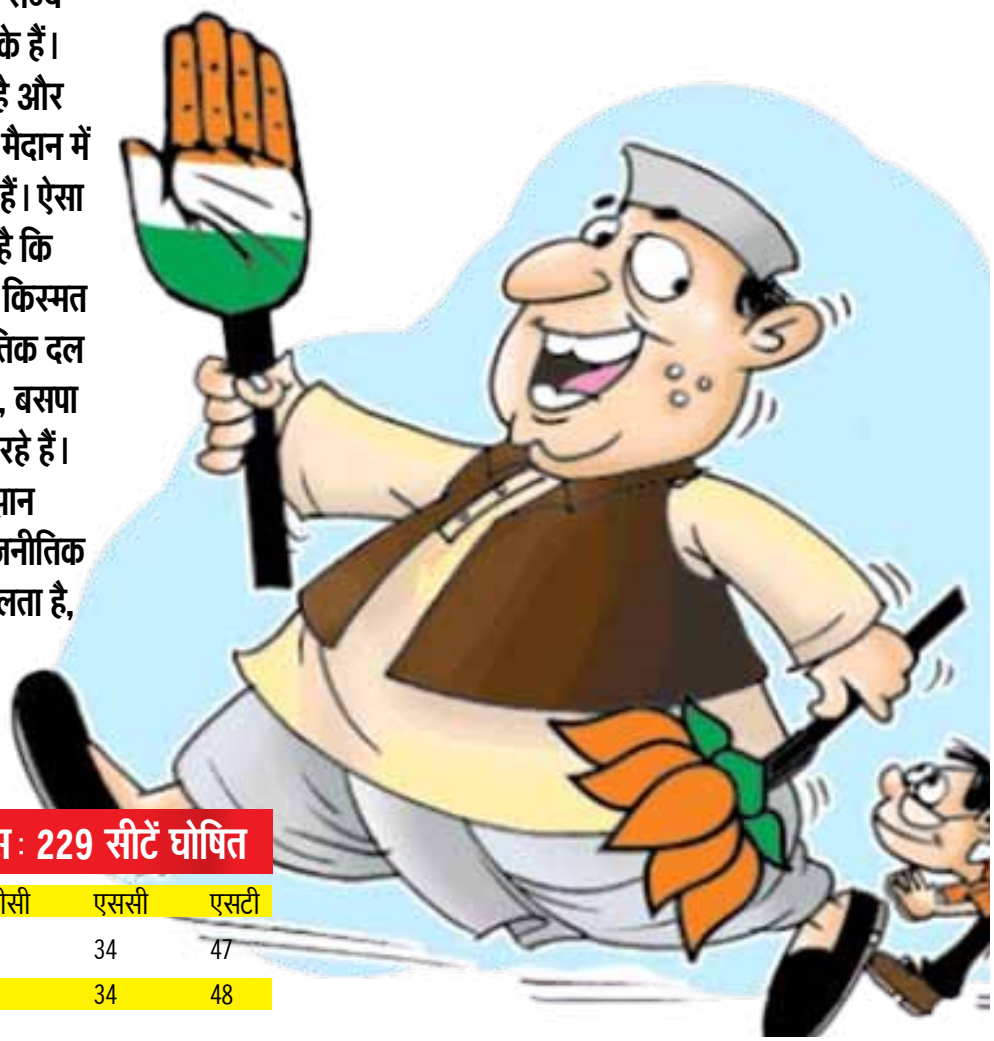

बीजेपी : 228 सीटें घोषित, कांग्रेस : 229 सीटें घोषित

पार्टी	युवा	महिला	ओबीसी	एससी	एसटी
बीजेपी	98	28	69	34	47
कांग्रेस	99	30	62	34	48

मध्यप्रदेश की 230 सीटों में से भाजपा ने 228 तो कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर देखने से भाजपा और कांग्रेस का टिकट बंटवारे का गणित एक जैसा ही है। वहीं आम आदमी पार्टी अब तक केवल 69 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ही कर पाई है। इस तरह उम्मीदवारों की घोषणा करने में आप पिछड़ गई है। सपा अब तक 42 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस से समझौता न होने के बाद पार्टी ने यहां करीब 50 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में 114 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है. कहा जा रहा है कि बसपा चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन भी किया है। बहुजन समाज पार्टी ने दावा किया है कि इस बार उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। बसपा का ने ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में पार्टी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी।

उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होते ही प्रदेश के दोनों सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी में बगावती स्वर उठने लगे हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिला वे रैलियां विरोध और निर्दलीय चुनाव लड़ने जैसे प्रयासों से अपनी दावेदारी जताने में जुटे है। पूर्व संसद नंदकुमार के पुत्र हर्षवर्धन निर्दलीय चुनाव लड़ सकते है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विधायकों के टिकट काटे हैं। वहीं कई दावेदारों की मंशा को पूरा नहीं होने दिया।

लिहाजा आक्रोश और असंतोष चरम पर पहुंच गया है। भाजपा की बात करें तो कई स्थानों पर पदाधिकारी ने इस्तीफा देने शुरू कर दिए हैं और दल बदल भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से न केवल संपर्क कर रहे हैं बल्कि उनकी सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। जबलपुर में तो अजब नजारा देखने को मिला, जहां केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और सुरक्षाकर्मी से अभद्रता भी की। इसके अलावा, कई स्थानों से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। एक तरफ जहां भाजपा में असंतोष उभर रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी नाराजगी लगातार बढ़ रही है और यही कारण रहा कि पार्टी को तीन उम्मीदवारों में बदलाव लाना पड़ा है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता तो प्रदेश कार्यालय भी पहुंच गए और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुतलों का दहन भी किया।

कांग्रेस और भाजपा में बढ़ते असंतोष और विरोध प्रदर्शन के चलते दोनों ही राजनीतिक दल चिंतित हैं। इस बार का चुनाव कांटे का है और हार जीत में ज्यादा अंतर न रहने की संभावना जताई जा रही है। टिकट वितरण में दोनों राजनीतिक दल निष्पक्षता और चुनाव जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारने का दावा कर रहे हैं तो वहीं असंतोष पर काबू करने की बात कह रहे हैं। आने वाले दिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती है।

कांग्रेस-सपा में नहीं बनी बात तो BJP ने कसा तंज, शिवराज बोले-

दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती...

शिवराज ने कहा कि जनता आश्चर्य के साथ इस गठबंधन को देख रही है कि आज जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा? दरअसल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों पूरी तैयारी में जुटे हुई हैं। इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्हीं के बायन पर भाजपा नेता और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। शिवराज ने कहा कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है?। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक साल तक धोखे में रखा। जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने (अखिलेश यादव) किया है, उससे उनके मन की स्थिति को समझा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा और AAP तीनों लड़ रहे हैं। ये किस बात का गठबंधन है?

शिवराज ने कहा कि जनता आश्चर्य के साथ इस गठबंधन को देख रही है कि आज जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा? दरअसल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। रात 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने जगाया और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे लेकिन जब सीटें घोषित की गईं तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर INDIA का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाते। समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार उनको (कांग्रेस) देखने को मिलेगा।

मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही यह खत्म हो चुकी है। दोनों राजनीतिक दलों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इसके बाद दोनों ओर से शब्द बाण भी एक-दूसरे के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सपा-कांग्रेस गठबंधन पर ब्रेक लगने से अखिलेश यादव नाराज है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर यह गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। कमलनाथ ने कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और अगर यह गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होता है तो अच्छा होता। कमलनाथ ने कहा कि चुनावी साझेदारी (सहयोगियों के साथ) में कुछ जटिलताएं हैं क्योंकि कांग्रेस को स्थानीय स्थिति पर विचार करना होगा। आप भी वहा अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में सपा-कांग्रेस गठबंधन नहीं होने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है और इसका सीधा कनेक्शन राजस्थान से है।

कांग्रेस आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री यहां मानिकसरा गांव में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। चौहान ने आरोप लगाया, ''कांग्रेस ने हमेशा गरीबों और आदिवासियों का शोषण किया है। कांग्रेस को आदिवासियों का 'दुश्मन' करार देते हुये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समुदाय के लोगों को जूते दिये जाने की राज्य सरकार की योजना पर सवाल उठाने लिए बृहस्पतिवार को पार्टी के नेता प्रियंका गांधी वाद्रा की आलोचना की। मुख्यमंत्री यहां मानिकसरा गांव में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। चौहान ने आरोप लगाया, ''कांग्रेस ने हमेशा गरीबों और आदिवासियों का शोषण किया है।

अगर किसी ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, तो वह कांग्रेस है, जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है और उसने कभी उनका सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा, ''हाल ही में, प्रियंका गांधी ने कहा कि मामा (चौहान) आदिवासियों को चप्पल और जूते पहना रहे हैं। हां, मैं ऐसा करना जारी रखूंगी। अगर किसी आदिवासी के पैर में कांटा चुभता है, तो वह मेरे दिल में भी चुभता है। चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासियों को जूते, पानी की बोतलें और 200 रुपये का छाता दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ऐसे कदम उठाना जारी रखेगी। विपक्षी दल पर हमला बोलते हुए, चौहान ने कहा, कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि मैं लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खातों में चुपचाप पैसा जमा करूंगा। उन्होंने इसके बारे में चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। गुप्त रूप से क्यों, मैं इसे खुले तौर पर करूंगा। उन्होंने कहा, वर्तमान में (योजना के तहत) 1.32 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,250 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। हमारी योजना इस राशि को 3,000 रुपये प्रति माह तक ले जाने की है। चौहान ने लोगों को कांग्रेस के जाल में फंसने के प्रति आगाह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया है।

अब ओलंपिक में फिर से खेला जाएगा क्रिकेट

128 सालों के बाद वापसी

इस सप्ताह की शुरुआत में, एलए 2028 खेलों के आयोजकों ने इस आयोजन में क्रिकेट, फ्लैग फ़ुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल-सॉफ्टबॉल को जोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। आईओसी के नियमों के अनुसार, प्रत्येक मेजबान शहर को खेलों के अपने संस्करण के लिए कई खेलों को शामिल करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने शुक्रवार, 13 अक्टूबर को 2028 लॉस एंजिल्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी। क्रिकेट 2028 खेलों के लिए एलए आयोजन समिति द्वारा अनुशंसित पांच खेल विषयों में से एक था और इसे मुंबई में अपनी कार्यकारी बैठक के दौरान शीर्ष ओलंपिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के साथ-साथ बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, फ़्लैग फ़ुटबॉल (नॉन-कॉन्टैक्ट अमेरिकन फ़ुटबॉल), स्क्वैश और लैक्रोस सहित चार नए खेल भी शामिल किए जाएंगे।

इस सप्ताह की शुरुआत में, एलए 2028 खेलों के आयोजकों ने इस आयोजन में क्रिकेट, फ़्लैग फ़ुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश और बेसबॉल-सॉफ़्टबॉल को जोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। आईओसी के नियमों के अनुसार, प्रत्येक मेजबान शहर को खेलों के अपने संस्करण के लिए कई खेलों को शामिल करने का अनुरोध करने का अधिकार है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने

कार्यकारी बोर्ड की बैठक के अंत में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'इन प्रस्तावों को आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने एक पैकेज के रूप में स्वीकार कर लिया है।' ओलंपिक में इन खेलों की स्थिति को अंतिम रूप देने में अगला कदम रविवार से शुरू होने वाला आईओसी सत्र होगा। आईओसी सत्र में बोर्ड की सिफारिश पर मुहर लगाने की आवश्यकता होगी।

दुनिया में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने की बात करते हुए आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि ओलंपिक समिति आईसीसी के साथ काम करेगी न कि किसी देश के व्यक्तिगत क्रिकेट अधिकारियों के साथ। उन्होंने कहा, 'आईसीसी के सहयोग से हम देखेंगे कि क्रिकेट को और अधिक लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है।' गौरतलब है कि भारत में क्रिकेट को बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल है। टीम खेल में वैश्विक स्तर पर दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। 128 साल बाद इस खेल की वापसी होने जा रही है। आखिरी बार ओलिंपिक में यह 1900 को खेला गया था।

राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी

विस निर्वाचन 2023 : धार्मिक स्थलों पर मंच नहीं बना सकेंगे उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार सामान्य आचरण के तहत किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए,जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या फिर तनाव कर स्थिति भी पैदा हो सकती है। मंदिर,मस्जिद,चर्च और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे,ताकि पुलिस शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे बैनर, झंडे

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि,भवन,परिसर की दीवारों आदि पर झंडा लगाने,बैनर लटकाने,सूचना चिपकाने,नारा लिखने आदि की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थियों द्वारा यह तय किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बॉटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए,जहां अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे।

जीवन के पहलुओं की आलोचना से बचें

यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए, तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों,गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी।

सायरन सहित कार के प्रयोग की अनुमति नहीं

मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट अथवा किसी भी प्रकार के सायरन सहित कार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी भले ही राज्य प्रशासन ने उसे सुरक्षा कवर दिया हो जिसमें ऐसे दौरों पर उसके साथ सशस्त्र अंगरक्षकों के उपस्थित रहने की आवश्यकता हो। यह निषेध सरकारी व निजी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा।

इन चीजों से भी बचने की आवश्यकता

मतदाताओं को घूस देना, डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना,मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं और मतदाताओं को वाहन उपलब्ध कराना।

लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मियों को मिलेगी बंपर खुशी

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में 'ओपीएस' का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में 'पे' रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।

डीए 50 प्रतिशत होने का मिलेगा ये फायदा

केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में 'ओपीएस' का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50 प्रतिशत या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 132.8 था। फरवरी में 132.7 रहा। मार्च में 133.3 हो गया। अप्रैल में 134.2 पर पहुंच गया। मई में 134.7 रहा। जून में छलांग लगाकर सीपीआई-आईडब्लू 136.4 पर पहुंच गया। जनवरी से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। जनवरी में डीए की दर 42 फीसदी और जुलाई में 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

अगस्त में 139.2 पर रहा सीपीआई-आईडब्लू

श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर 16 महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है। अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्लू) 0.5 अंक घटकर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.36 प्रतिशत की कमी रही। एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी

संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया था कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए डीए/डीआर दिया जाता है। अब डीए 42 प्रतिशत हो गया है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा हो गई।

केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद, डीए 51 % तक पहुंचेगा

अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके डीए की दर 51 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। जनवरी 2024 में सरकार इसे पांच फीसदी तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी एवं भत्ते रिवाइज हो जाएंगे। जुलाई 2023 में सीपीआई-आईडब्लू 139.7 पर रहा था। अगस्त में वह 139.2 अंकों पर संकलित हुआ। सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर में सीपीआई-आईडब्लू 140.2 रह सकता है। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में पांच फीसदी डीए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को आठवां पे कमीशन गठित करना होगा। सातवाँ वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी।

जजों को करना होगा अनुशासन का पालन, चीफ जस्टिस के निर्देश के बिना न करें सुनवाई...

राजस्थान हाई कोर्ट ने मई में अपने एक आदेश में निर्देश दिया था कि आठ प्राथमिकियों के संबंध में तीन व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायधीशों को सख्त हिदायत दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। साथ ही किसी भी मामले को तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से न सौंपा गया हो। शीर्ष कोर्ट की न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से नहीं सौंपे गए मामले को उठाने को शीर्ष कोर्ट ने 'घोर अनुचितता का कार्य' बताया। शीर्ष अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को एक साथ जोड़ने के लिए एक सिविल रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है।

दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट ने मई में अपने एक आदेश में निर्देश दिया था कि आठ प्राथमिकियों के संबंध में तीन व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि तीन व्यक्तियों ने पहले एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।

इसके बाद, उन्होंने आठ एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें एक में समेकित करने के लिए एक अलग सिविल रिट याचिका दायर की। अपीलकर्ता अंबालाल परिहार जिनकी शिकायत पर तीनों व्यक्तियों के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की गईं, ने शीर्ष अदालत के समक्ष दावा किया कि सिविल रिट याचिका दायर करना एक पैंतरा था ताकि अंतरिम राहत नहीं देने वाले रोस्टर जज से बचा जा सके।

यह फोरम हंटिंग का उत्कृष्ट मामला

पीठ ने 16 अक्तूबर के फैसले में कहा, यह फोरम हंटिंग का उत्कृष्ट मामला है। यह कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का भी मामला है। इस तरह के पैंतरों को मंजूरी दी जाती है तो फिर चीफ जस्टिस के रोस्टर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जजों को अनुशासन का पालन करना होगा और किसी भी मामले में तब तक सुनवाई शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक कि चीफ जस्टिस उन्हें विशेष रूप से वह मामला नहीं सौंपें। पीठ ने कहा, न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं, बशर्ते कि या तो उस श्रेणी के मामले अधिसूचित रोस्टर के अनुसार उन्हें सौंपे गए हों या चीफ जस्टिस खासतौर से कोई विशेष मामला उन्हें सौंपें। पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि इस मामले में एक सिविल रिट याचिका दायर की गई थी, लेकिन जज को इसे आपराधिक रिट याचिका में परिवर्तित कर देना चाहिए था, जिसे आपराधिक रिट याचिकाएं लेने वाले रोस्टर जज के समक्ष ही रखा जा सकता था।

याचिकाकर्ताओं पर 50 हजार का जुर्माना भी

पीठ ने कहा, हमें यकीन है कि तीनों वादियों के इस आचरण पर संबंधित अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करेगी। यह एक उपयुक्त मामला है जहां तीनों व्यक्तियों को 50 हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा। यह राशि एक महीने के भीतर राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भुगतान करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपसे गलती हुई थी...

डाक विभाग को मिला शख्स को 28 साल बाद नौकरी देने का आदेश

एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 साल बाद नौकरी मिली है। दरअसल अंकुर गुप्ता नाम के शख्स ने साल 1995 में डाक सहायक (Postal Assistant) के पद के लिए आवेदन किया था। प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद में अंकुर को इस आधार पर मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया कि उन्होंने वोकेशनल स्ट्रीम से 12वीं की शिक्षा पूरी की थी।

एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 साल बाद नौकरी मिली है। दरअसल, अंकुर गुप्ता नाम के शख्स ने साल 1995 में डाक सहायक (Postal Assistant) के पद के लिए आवेदन किया था। प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद में अंकुर को इस आधार पर मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया कि उन्होंने 'वोकेशनल स्ट्रीम' से 12वीं की शिक्षा पूरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अंकुर गुप्ता की नियुक्ति का आदेश दे दिया कि उसे इस पद के लिए अयोग्य ठहराने में गलती हुई है। मेरिट लिस्ट से बाहर होने के बाद अंकुर गुप्ता अन्य असफल उम्मीदवारों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चले गए, जिसने 1999 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, यह फैसला डाक विभाग को रास नहीं आया और उसने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए साल 2000 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने साल 2017 में याचिका खारिज कर दी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। वहीं, हाई कोर्ट में एक समीक्षा दायर की गई थी जिसे 2021 में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद डाक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को शुरुआती चरण में खारिज नहीं किया गया और सलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने दिया गया। अंततः उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी आया है। तो वह इसलिए उम्मीदवारी का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। उसके पास निपक्ष व्यवहार के लिए सीमित अधिकार होते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि डाक विभाग अगर संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है, को मनमाने तरीके से काम करने और उम्मीदवार को बिना किसी कारण के बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर डाक विभाग ने अंकुर गुप्ता को शैक्षिक योग्यता की शुरूआती समय में ही अयोग्य घोषित कर दिया होता, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती।

राजनाथ की चीन सीमा पर हुंकार, कहा- देश में ही बनेंगे सभी प्रमुख हथियार...

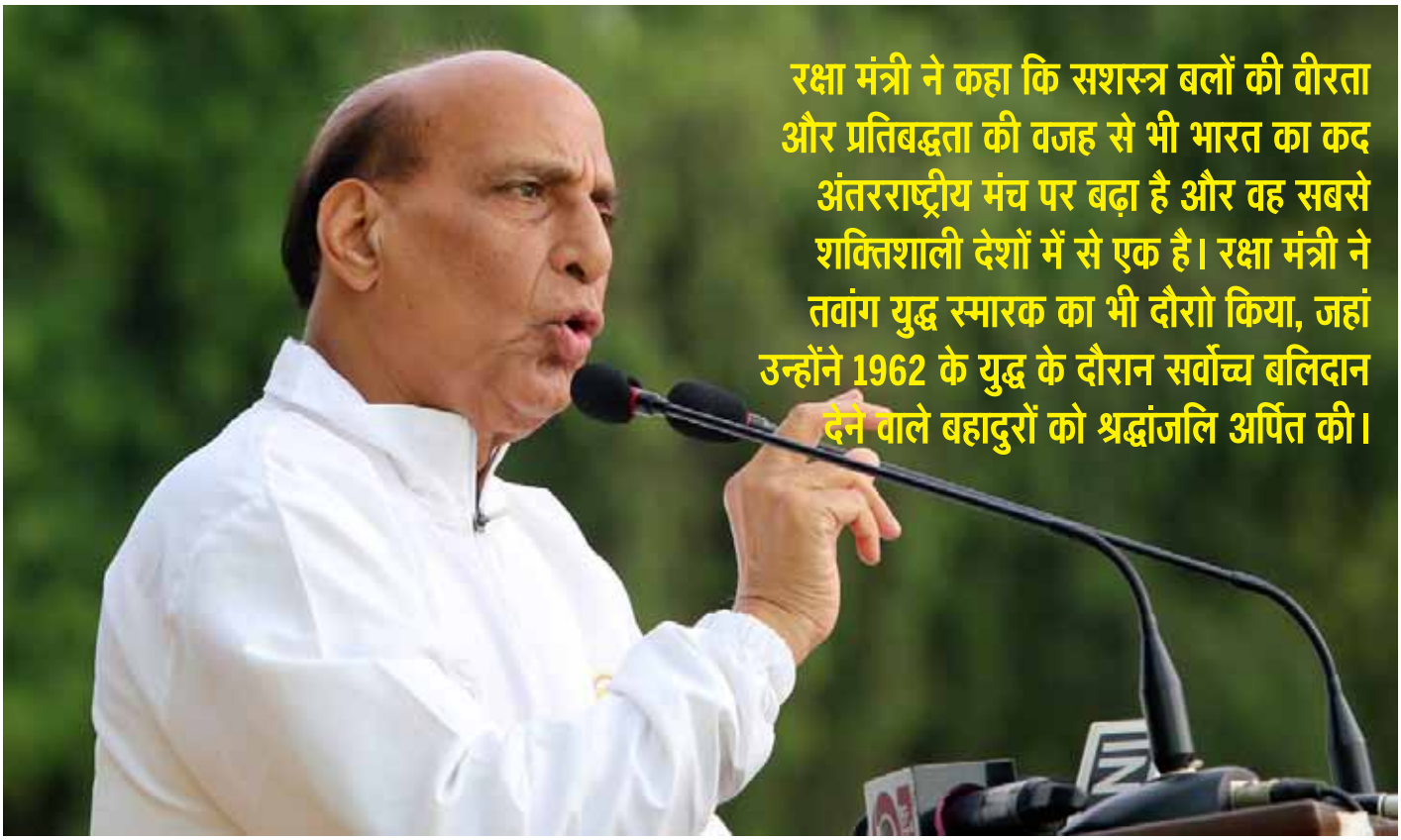

रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों की वीरता और प्रतिबद्धता की वजह से भी भारत का कद अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ा है और वह सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक का भी दौरा किया, जहां उन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सभी प्रमुख हथियार और प्लेटफॉर्म भारत में ही बनें। रक्षा मंत्री दशहरे के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शस्त्र पूजन करने के बाद सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे। चीन से लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच राजनाथ ने तवांग में अग्रिम चौकियों का दौरा किया। सैनिकों से बातचीत के दौरान राजनाथ ने उनकी अडिग भावना, अटूट प्रतिबद्धता और अद्वितीय साहस के प्रति आभार जताया, जो कठिन परिस्थितियों में सीमाओं पर तैनात हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि देश और उसके नागरिक सुरक्षित रहें।

उन्होंने कहा, पूरे देश को सशस्त्र बलों पर गर्व है और वह उनके साथ खड़ा है। राजनाथ ने सशस्त्र बलों के जवानों की धार्मिकता और धर्म को विजयदशमी के त्योहार के लोकाचार का जीवित प्रमाण बताया। इससे पहले, सोमवार शाम को रक्षा मंत्री ने असम के तेजपुर में 4 कोर मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की, जो देश के एकदम पूर्वी हिस्सों में से एक में तैनात है। रक्षा मंत्री को एलएसी पर बुनियादी ढांचे के विकास और अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिकों की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।

सशस्त्र बलों ने बढ़ाया देश का कद

रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों की वीरता और प्रतिबद्धता की वजह से भी भारत का कद अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ा है और वह सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक का भी दौरा किया, जहां उन्होंने 1962 के युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी थे।

द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने दिखाई ताकतः जवानों से बातचीत के दौरान अपने हालिया इटली दौरे का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने मोंटोन स्मारक (पेरुगिया प्रांत) का दौरा किया, जिसे नाइक यशवंत घाडगे और अन्य भारतीय सैनिकों के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटोन को मुक्त कराने के इतालवी अभियान में शामिल थे। उन्होंने कहा कि न केवल भारतीय, बल्कि इतालवी भी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, जो इसका प्रमाण है कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का लोहा दुनिया भी मानती है।

रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता घटीः रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से देश की सैन्य शक्ति मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। पहले हम अपनी सेना को उन्नत करने के लिए आयात पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब प्रमुख हथियारों और प्लेटफार्मों का निर्माण देश के भीतर ही किया जा रहा है।

करोड़ों रुपये की सैन्य सामग्री कर रहे निर्यात

रक्षा मंत्री ने कहा, विदेशी कंपनियों को अपनी तकनीक साझा करने और घरेलू उद्योग के साथ भारत में उपकरण का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2014 में रक्षा निर्यात का मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रुपये था, लेकिन आज हम हजारों करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। बच्चों में यह कमी उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधक है। ऐसे में हम सबको मिलकर बच्चों के विकास के लिए उनके खाने में विटामिन, आयरन आदि की मात्रा बढ़ानी होगी।

हर तीन महीने के बाद मेन्यू में बदलाव करें: वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हर तीन महीने के बाद मेन्यू में बदलाव करें, ताकि बच्चों के खाने में नयापन रहे। इसके लिए रसोइयों और शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाएं। अभिभावकों को भी साथ में रखें, ताकि उनके सुझाव पर काम हो सके। इसमें डाइटिशियन भी मदद ली जा सकती है।

पितृ पक्ष एकादशी : सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि...

आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्योतिष के कुछ उपाय करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में... पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इस बार यह शुभ तिथि 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करने से पितर भी तृप्त हो जाते हैं। साथ ही पितरों के नाम पर किए गए दान से उनको मोक्ष प्राप्त होता है और व्रत करने वाले को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए...

एकादशी के इस उपाय से मनोकामना होगी पूरी : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ को दूध से सीचें और सरसों के तेल का दीपक जाएं। फिर पांच तरह की मिठाई अर्पित करें और वृक्ष के नीचे ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और अपनी मन की मनोकामना के बारे में अवगत कराएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से अटके कार्य पूरे होते हैं।

इस उपाय से पितर देंगे आशीर्वाद

इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन पूरे मन से व्रत रखकर पितरों के नाम का दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराएं और शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होकर परिजनों का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पितृ दोष भी दूर होता है।

पितरों को होगी मोक्ष की प्राप्ति

कष्टों से मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर सुबह शाम तुलसी की माला से 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और भोग लगाते समय तुलसी पत्ता डालकर नैवेद्य अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं।

एकादशी के इस उपाय से सभी संकट होंगे दूर

पितृपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितरों को याद करते हुए 11 घी के दीपक से तुलसी पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर ही इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद शाम के समय घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हर प्रकार का संकट टल जाता है।

एकादशी के इस उपाय से होगी उन्नति

इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने के बाद पांच लोगों के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पहला गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। साथ ही चीटियों को आटा भी डालें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है।

आखिर कुंडली में क्यों लगता है पितृदोष..?

कुंडली में पितृ दोष लगना काफी अशुभ माना जाता है। इसके लगने से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर कुंडली में पितृ दोष क्यों लगता है और इसके अशुभ प्रभावों को रोकने के क्या उपाय हैं? कुंडली में पितृदोष लगने से व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम काफी घातक होते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। गर्भधारण में कई तरह की समस्याएं आती हैं। व्यक्ति जीवन भर अपनी जिंदगी में उतार-चढ़ाव का सामना करता है। मान्यता है कि जो लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते और मृत्यु के बाद अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते। उनके अगले जन्म के जीवन में कुंडली के अंदर पितृ दोष पाया जाता है। यदि आपके जीवन में भी कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है और रास्ते में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है। ऐसे में आपको अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को जरूर दिखानी चाहिए। जिसके प्रभाव से जीवन में हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं. घर में हमेशा किसी का बीमार रहना, मान-सम्मान की हानि, पिता से विवाद, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना या फिर बने बनाए काम का बिगड़ जाना. यह लक्षण कुंडली में सूर्य के कमजोर होने का संकेत हैं. यह चीजें इस तरफ भी इशारा करती हैं कि आपके कुंडली में पितृ दोष है.

सूर्य और चंद्रमा की कमजोर स्थिति

सूर्य को पिता का ग्रह माना जाता है. कुंडली में सूर्य कमजोर या पीड़ित हो तो पितृ दोष के संकेत मिलते हैं. अगर सूर्य कमजोर है तो जीवन में मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेती हैं. ऐसे में सूर्य को मजबूत करने के उपाय किए जाने चाहिए. वहीं कुंडली में चंद्रमा को मां का ग्रह माना जाता है. कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने से भी पितृ दोष लगता है. चंद्रमा के कमजोर होने से मातृ पक्ष में समस्याएं होने लगती हैं. कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए और चंद्रमा को मजबूत बनाने के उपाय आजमाने चाहिए. सूर्य और चंद्रमा के मजबूत होने से पितृ दोष नहीं लगता है.

राहु भी बनाता है पितृ दोष

राहु एक छाया ग्रह है और जीवन में बाधाएं और चुनौतियां लेकर आता है. अगर कुंडली में राहु नौवें स्थान पर स्थित हो, तो यह पितृ दोष का संकेत देता है. इस स्थिति में आप जो भी नया काम शुरू करते हैं उसमें असफलता ही मिलती है. राहु की वजह से कोई भी काम पूरा करने में समस्या आती है. कई बार बने-बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार पूर्वजों के किए पाप का फल उनके वंशजों को भोगना पड़ता है. यह वंशज की कुंडली में पितृ दोष के रूप में आता है. वहीं वंशज अगर पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, उनका सही से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते हैं तो इससे भी पितृ दोष होता है. ऐसे में पूर्वजों का विधि पूर्वक तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

पितृदोष के अशुभ प्रभावों को रोकने के कई उपाय हैं। आइए जानते हैं -

पितृ दोष निवारण मंत्र - "ॐ श्रीं सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशं हं हं सुख शांतिम् देहि फट् स्वाहा"।

'ॐ पितृभ्य देवताभ्य महायोगिभ्येच च, नमः
स्वाहा स्वाध्याय च नित्यमेव नमः'।

पितृ दोष के प्रभाव को कम करने के लिए महादेव की मूर्ति के सामने इस मंत्र (ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात) का जाप करें। अपने पितरों की मुक्ति के लिए श्रद्धापूर्ण ढंग से प्रार्थना करें। ऐसे में पितृ दोष का प्रभाव जीवन से धीरे-धीरे कम होने लगेगा और जीवन में आने वाली कई दिक्कतें अपने आप हट जाएंगी।

यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जहां पर एक पीपल का वृक्ष हो। वहां जाकर आप पीपल के वृक्ष पर दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। इसके अलावा शाम के वक्त मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन से कई सारे दुखों का निवारण होने लगता है।

अमावस्या के दिन गाय को पांच तरीके से जरूर फल खिलाएं। इसके साथ बबूल के पेड़ के नीचे भोजन को रखें। अमावस्या के दिन आप पितरों के लिए पवित्रता के साथ भोजन बनाएं। इसके अलावा चावल बूरा, घी और एक रोटी गाय और कौआ को खिलाएं। पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी और सफेद कपड़ा मंदिर में गरीब और असहाय लोगों को दान दें। इससे पितृ खुश होते हैं और जीवन में आने वाली कई अड़चनें खत्म हो जाती हैं और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है।

पूजा के बाद अपने पितरों से आपसे हुई भूल-चूक की क्षमा मांगे। ऐसे में पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पाया जाने वाले पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है।

पूर्वजों द्वारा किए गए पिछले पापी कार्यों के प्रभावों को खत्म करने के लिए पूर्ण त्रिपिंडी श्रद्धा ने पूजा या मंत्र जाप का आयोजन किया।

प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराएं।

अर्ध-कुंभ-स्नान के दिन भोजन, वस्त्र, कंबल का दान करें।

वट वृक्ष पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं।

गाय, गली के कुत्तों और जानवरों को भोजन और दूध दें।

जितना संभव हो सके जरूरतमंद गरीबों और वृद्ध लोगों की मदद करें।

देवी कालिका स्तोत्रम् के मंत्रों का जाप करें। खासतौर पर नवरात्रि पर.

हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गंगासागर आदि विभिन्न धार्मिक स्थानों पर स्नान करें।

नियमित रूप से उगते सूर्य को तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें।

शांत मन संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है

वह रात को झोपड़ी में एक छोटा सा दीया जलाकर शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। थकान के साथ जब नींद आने लगी तो उसने फूंक मार कर दीया बुझा दिया। वह यह देख कर हैरान हो गया कि दीया बुझते ही झोपड़ी में चांदनी बिखर गई। सोच में पड़ गया कि यह चांदनी अब तक उसे क्यों नहीं दिखाई दी? क्या एक छोटे से दीए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था?

इस प्रश्न का जवाब झोपड़ी के साथ उसके मन को भी आलोकित कर गया। सोचने लगा कि मैंने तो अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के एक नहीं, अनेक छोटे-छोटे दीए जला रखे हैं। शायद इसी कारण परमात्मा रूपी चांद का आलोक मेरे मन-मंदिर के बाहर ही खड़ा रह जाता है। मेरे मन के ये दीए दिखते तो जरा-जरा से हैं, लेकिन इनकी लौ से सब कुछ राख हो जाता है। कामनाएं सुख, चैन सब छिन जाते हैं। क्रोध जघन्य अपराध का जनक है। अहंकार का ही परिणाम संबंधों में विघटन, वर्ग संघर्ष, अमीरी-गरीबी भेदभाव हैं। मायावी का व्यवहार सरल और सहज नहीं होता और लोभ तो अनर्थों का मूल और हिंसा जैसे दोषों की खान है।

यह राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ-मोह जैसा विकार जीव का बंधन है। विवेक से इसे तोड़ना जीव का ही काम है। इस काम में सहयोगी होता है मन, जिसे वश में करना है। वास्तव में मानव मन में विषयों की आसक्ति है। मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य अंत में उस परमेश्वर की प्राप्ति ही है, लेकिन परमेश्वर कोई ऐसा फल नहीं है जिसे कोई भी तोड़कर किसी के मुख में डाल दे। इनमें से कोई न कोई विकार हमें प्रभु के रास्ते से भटका ही देता है। गले की प्यास पानी के हर घूंट पर कम होती जाती है, जबकि मन की प्यास प्रत्येक सामग्री की उपलब्धि पर बढ़ती जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक प्रखर, नियंत्रित और शांत मन संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक है।

उस व्यक्ति ने तो थकान और नींद के कारण दिया बुझाया। लेकिन हमें नींद से जाग कर चैतन्य होकर विकारों के इन छोटे-छोटे दीयों को बुझाने होंगे, ताकि परमेश्वर रूपी पूर्णचंद्र की आभा का हमारे हृदय में प्रवेश हो।

जानें किसके तर्पण के समय किस मंत्र का करें जाप...

पितृ पक्ष में पितरों को तर्पण करने की परंपरा है, तर्पण के समय इससे जुड़े मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से तर्पण का पूरा लाभ मिलता है।

पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण करने का पक्ष पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू चुका है। पितरों को तर्पण अर्थात जलांजलि देते समय नीचे दिए गए मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। जिस पितर को जलांजलि दे रहें हैं। उससे जुड़े मन्त्रों का ही उच्चारण करना चाहिए। माता –पिता और दादा –दादी से जुड़े मंत्र नीचे दिए गए हैं।

पिता जी को तर्पण करते समय

पिता जी को तर्पण करने के पहले एक बर्तन में गंगा जल या अन्य जल में दूध, तिल और जौ मिलाकर रखें, इसके बाद अंजलि में जल लेकर तीन बार पिता को जलांजलि दें। जल देते समय अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, गोत्रे अस्मतपिता (पिता जी का नाम) शर्मा वसुरूपत् तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।

माता जी के तर्पण के लिए मंत्र

जलांजलि देते समय अपने गोत्र का नाम लेते हुए (गोत्र का नाम) कहें -गोत्रे अस्मन्माता (माता का नाम) देवी वसुरूपास्त् तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।

दादा जी के तर्पण के लिए मंत्र

दादा जी को जलांजलि देते समय अपने गोत्र का नाम लेते हुए बोलें, गोत्रे अस्मत्पितामह (दादा जी का नाम) शर्मा वसुरूपत् तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः।

दादी के तर्पण में जल देने का मंत्र

दादी जी को जलांजलि देते समय अपने गोत्र का नाम लेते हुए बोलें- गोत्रे पितामां (दादी का नाम) देवी वसुरूपास्त् तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जल वा तस्मै स्वधा नमः,तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः

पितृ गायत्री मंत्र

यदि आप उपरोक्त मन्त्रों को पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए पितृ गायत्री पाठ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पितृ गायत्री मंत्र पढ़ने से भी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

पितृ गायत्री मंत्र :

1. ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृो प्रचोदयात्। 2. ॐ देवताभ्य : पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नम : स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम : । 3. ॐ आद्य-भूताय विद्महे सर्व-सेव्याय धीमहि। शिव-शक्ति-स्वरूपेण पितृ-देव प्रचोदयात्।

मृत्यु तिथि मालूम न हो तो अमावस्या पर करें धूप-ध्यान

पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने का महापर्व पितृपक्ष 14 अक्टूबर (सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या) तक चलेगा। पितृ पक्ष में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और धूप-ध्यान आदि धर्म-कर्म संतान द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी मृत सदस्य की संतान न हो तो उसके रिश्तेदार श्राद्ध कर्म कर सकते हैं।

उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के मुताबिक, पितृपक्ष में हमें अपने घर-परिवार के मृत सदस्यों का मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ऐसा करने से पितृ ऋण उतरता है।

पितृपक्ष से जुड़ी खास बातें...

- शास्त्रों में तीन तरह के ऋण बताए गए हैं- देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पूजा-पाठ करने से देव ऋण उतरता है। दान-पुण्य करने से ऋषि ऋण उतरता है और श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण उतरता है।
- पितृ पक्ष में मृत गुरु, सास-ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, दामाद, भानजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र का भी श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध इनकी मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या (14 अक्टूबर) पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए।
- माता-पिता और घर के बड़े-बुजुर्ग अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं। संतानों का भी कर्तव्य होता है कि वे भी बड़ों के सुख का ध्यान रखें। घर के लोगों की मृत्यु के बाद उनके लिए श्राद्ध कर्म करना संतान का कर्तव्य है। घर-परिवार के मृत सदस्य को ही पितर देवता माना जाता है। इनके लिए श्राद्ध और दान-पुण्य जरूर करना चाहिए।
- किसी मृत व्यक्ति की संतान भी न हो तो उसके रिश्तेदारों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति के एक से ज्यादा पुत्र हैं और सभी एक साथ ही रहते हैं तो सबसे बड़े बेटे को श्राद्ध करना चाहिए। अगर बच्चे अलग-अलग रहते हैं तो सभी अपने-अपने घर में अलग-अलग धूप-ध्यान कर सकते हैं।
- मृत व्यक्ति का कोई पुत्र न हो तो पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है और उसकी कोई संतान भी नहीं है तो वह खुद अपने पति के लिए श्राद्ध कर सकती है।
- किसी मृत व्यक्ति की पत्नी भी नहीं है तो उसका जीवित भाई श्राद्ध कर सकता है। पुत्र की संतान अपने दादा-दादी के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती है।
- पुरुष अपनी पत्नी का श्राद्ध तब ही कर सकता है जब उसकी कोई संतान न हो। पुत्र, पौत्र, पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। अगर गोद लिया हुआ पुत्र है या दामाद है तो वह भी श्राद्ध कर सकता है।

अशुभ नहीं होता श्राद्ध पक्ष, योग देखकर कर सकते हैं खरीदारी

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस साल 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और इनका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगा।

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस साल 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और इनका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगा। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इस दौरान खरीदारी करना अशुभ होता है। लेकिन, ज्योतिषियों के अनुसार श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानना सही नहीं है। ऐसे में खरीदारी करना भी अशुभ नहीं होता, बल्कि इसे शुभ व फलदायी ही माना गया है। जो श्रेष्ठ योग व मुहूर्त आएं उसमें खरीद करना शुभ होता है। आगामी शादी ब्याह को देखते हुए खरीदारी करने में भी श्राद्ध पक्ष की कोई कोई बाधा नहीं है। खरीद की जा सकती है। वर्तमान में बाजार में खरीदारी का माहौल भी देखने को मिल रहा है।

मांगलिक आयोजन नहीं किए जाएं

पं. दिवाकर के अनुसार पितृ पक्ष अशुभ काल नहीं है। ये पित्तरों को समर्पित दिन होते हैं। ऐसे में पितरों की पूजा, तर्पण, दान करने से पुण्यदायी फल मिलता है। वहीं, इस दौरान खरीदारी करने से अशुभ होता है, ऐसा नहीं है। खरीदारी की जा सकती है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि बड़े-बड़े मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही करने चाहिए।

सर्वार्थसिद्धि व रवि पुष्य योग 8 को

पं. जगदीश दिवाकर के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कई बड़े शुभ योग बनते हैं जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, द्विपुष्कर व त्रिपुष्कर रवि आदि। तो ऐसे में खरीदारी व कोई अन्य शुभ कार्य करने हों तो शुभ योग देखकर ही वह कार्य करें। जैसे व्यापार संबंधित कार्य, लेनदेन, मकान, भूमि, वाहन, आभूषण आदि का लेनदेन किया जा सकता है। इस बार श्राद्ध पक्ष में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग दोनों बन रहे हैं। ये योग 1 से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य बनेंगे तब खरीदारी की जा सकती है।

जानिए कब-कौन से योग

सर्वार्थ सिद्धि योग : 1, 3, 4, 6, 8 अक्टूबर

रवि पुष्य योग : 8 अक्टूबर

भारत के सबसे अमीर मंदिर... करोड़ों का आता है दान...

हमारे देश में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए के हीरे-जेवरात के अलावा सोने के गहने व रुपए हैं। यह मंदिर लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। इस आर्टिकल में हम आपको देश के 5 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। पुराने समय से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हालांकि एक समय था, जब हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटने में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन इसके बाद भी देश में कई ऐसे मंदिर हैं। जिनमें करोड़ों रुपए से लेकर अरबों रुपए तक के सोना, चांदी और हीरे जेवरात रखे हुए हैं। यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। न सिर्फ दर्शन बल्कि भक्त मंदिर में लाखों का सोना और रुपए भी चढ़ाते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश के कुछ अमीर मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं।

तिरुपति बालाजी मंदिर

आंध्र प्रदेश के चित्तूर के तिरुमाला पर्वत पर मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यह जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां पर भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस मंदिर में रोजाना करीब लाखों रुपए का चढ़ावा मिलता है। वहीं साल में करीब 650 करोड़ रुपए का दान भक्तों द्वारा किया जाता है। इस मंदिर के पास 9 टन सोना और 14 हजार करोड़ रुपए की एफडी है।

पद्मनाभ स्वामी मंदिर

केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हर साल लाखों-करोड़ो का चढ़ावा चढ़ता है। इस मंदिर को देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोना आदि शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंदिर की 6 तिजोरियों में करीब 20 अरब डॉलर की चीजें रखी हुई हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति सोने से बनाई गई है। इस मूर्ति की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ के आसपास है।

शिरडी साईं बाबा मंदिर

मुंबई में स्थित शिरडी के साईं मंदिर में हर साल 900 करोड़ का चढ़ावा आता है। कोविड महामारी से पहले इसका रेवेन्यू करीब 800 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार मंदिर के राजस्व का रिकॉर्ड टूट गया है। मंदिर परिसर में रखी हुई दान पेटी से 200 करोड़ रुपए सिर्फ नगद निकाले गए हैं। इसके अलावा मंदिर में ऑनलाइन गिफ्ट, ज्वेलरी आदि के तौर पर कुछ न कुछ चढ़ावा आता रहता है। हाल फिलहाल मंदिर कमेटी ने बैंक में 2500 करोड़ रुपए जमा किए थे।

मां वैष्णों देवी

भारत के सबसे फेमस मंदिर में वैष्णों देवी मंदिर का नाम भी शामिल है। न सिर्फ यह मंदिर फेमस है, बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। बता दें कि इस मंदिर में हर साल करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। जिसके कारण यह मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल हैं। यहां पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारत का सबसे अमीर मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर है। इस मंदिर में न सिर्फ आम भक्त बल्कि बड़े-बड़े सिलेब्रिटी भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में बड़ी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धि विनायक मंदिर में 3.7 किलोग्राम सोने की कोटिंग की गई है। यह सोना कोलकाता के एक व्यापारी द्वारा दान किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल इस मंदिर में करीब 125 करोड़ रुपए का दान आता है।

विदेशों में कहां-कहां है भगवान श्री गणेश की प्रतिमा

अमेरिका के प्रमुख गणेश मंदिर

- फ्लोरिडा स्थित गुजरात समाज हिन्दू मंदिर।
- एरिजोना के फीनिक्स शहर स्थित महागणपति मंदिर।
- ऊटाह की सॉल्टलेक सिटी स्थित श्री गणेश मंदिर।
- सीएटेल स्थित श्री गणेश मंदिर।
- अलास्का स्थित श्री गणेश मंदिर।
- उत्तरी टेक्सास स्थित श्री गणेश मंदिर।
- कैलीफोर्निया के सेंट जोज स्थित वैदिका विद्या गणपति मंदिर।

श्रीलंका के गणेश मंदिर

- नल्लूर स्थित कैलाश पिल्लईयर मंदिर।
- चुलीपुरम स्थित कन्नईकोठीकक्कई पिल्लईयर मंदिर।
- इनूवी स्थित करुणाकर पिल्लईयर मंदिर।
- कोलंबो स्थित श्री मुथु विनायक मंदिर।
- नीरवेली स्थित अरासकेसरी पिल्लईयर मंदिर।
- मुरुकंडी स्थित पिल्लईयर मंदिर।

नेपाल के गणेश मंदिर

- काठमांडू स्थित अशोक विनायक, चन्द्र विनायक मंदिर।
- चोबर स्थित जल विनायक मंदिर।
- बुंगामाटी स्थित कर्ण विनायक मंदिर।
- जनकपुर स्थित सिद्ध गणेश मंदिर।
- फुलहारा स्थित गिरजा गणेश मंदिर।
- गोरखा स्थित विजय गणपति मंदिर।
- भक्तपुर स्थित सूर्य विनायक मंदिर।

सिंगापुर के गणेश मंदिर

- 19 सेलॉन रोड स्थित श्री सेगपंग विनायक मंदिर।
- 78 केओंग सिआक रोड स्थित श्री विनायक मंदिर।

कनाडा के प्रमुख गणेश मंदिर

- टोरंटो स्थित मुथु विनयागर कोविल मंदिर।
- टोरंटो स्थित रिचमंड हिल गणेश मंदिर।
- ब्रैंपटन स्थित श्री कटपक विनयागर रोविल मंदिर।
- एडमॉनटन स्थित श्री महागणपति मंदिर।

मलेशिया के गणेश मंदिर

- कोट्टूमलाई स्थित श्री गणेश मंदिर।
- जलान पुडु लामा स्थित श्री गणेशन मंदिर।
- इपोह स्थित श्री महागणपति मंदिर।
- इपोह स्थित श्री परमज्योति विनायक मंदिर।

नॉर्वे का गणेश मंदिर

- ट्रोंडेम स्थित गणेश हिन्दू मंदिर।

फ्रांस का गणेश मंदिर

- पेरिस स्थित श्री मणिकविनयकर आलयम मंदिर।

इंग्लैंड के गणेश मंदिर

- लंदन स्थित श्री गणपति मंदिर।
- विंबलडन स्थित गणपति मंदिर।
- थॉर्नटन स्थित श्री शक्ति गणपति मंदिर।

दक्षिण अफ्रीका के गणेश मंदिर

- डर्बन स्थित सिद्धिविनायक मंदिर। • लेडीस्मिथ स्थित गणेश मंदिर। • माउंट एजकोंब स्थित गणेश मंदिर।

ऑस्ट्रेलिया के गणेश मंदिर • ब्रिस्बेन स्थित श्री सेवा विनायक मंदिर।

- अडेलाएड स्थित गणेश मंदिर।
- मेलबोर्न स्थित श्री वक्रतुंड विनायक मंदिर।

कंबोडिया का गणेश मंदिर

- कंडाला स्थित पद्मासन गणेश मंदिर।

जर्मनी के गणेश मंदिर

- हैम स्थित सिद्धिविनायक मंदिर।
- हेलबॉर्न स्थित विनायक मंदिर।

कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है कच्चा पपीता...

पका हुआ पपीते का सेवन तो आप सभी करते ही होंगे। लेकिन बहुत कम लोग ही कच्चा पपीता अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हांलाकि कच्चे पपीते के सेवन से आपको कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आपको बता दें कि कच्चा पपीता ना सिर्फ पेट के लिए हेल्दी होता है, बल्कि यह अर्थराइटिस के दर्द को भी कम करने में मदद करता है। पका हुआ पपीते का सेवन तो आप सभी करते ही होंगे। लेकिन बहुत कम लोग ही कच्चा पपीता अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हांलाकि कच्चे पपीते के सेवन से आपको कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आपको बता दें कि कच्चा पपीता ना सिर्फ पेट के लिए हेल्दी होता है, बल्कि यह अर्थराइटिस के दर्द को भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन्स हमें कई गंभीर बीमारियों से दूर रखता है। आप चटनी, सब्जी या फिर सलाद के तौर पर कच्चे पपीते का सेवन कर सकते हैं।

कच्चे पपीते में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो सेहत के लिहाज से काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कच्चे पपीते में प्रोटीन, फोलेट, मैगनीशियम, विटामिन ए, सी, ई, पोटैशियम, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और कई अन्य एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीफेनॉल्स, लाइकोपीन, कैरोटेनॉएड्स और कई तरह के अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कच्चा पपीता खाने के लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं।

कच्चा पपीता खाने के लाभ

• कच्चा पपीता डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण इलाज का काम करता है। इसके सेवन से खून में शुगर की मात्रा कम होती है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। डायबिटीज के मरीजों को कच्चे पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए।

• कच्चे पपीते में विटामिन ई, अमीनो एसिड और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पायी जाती है। इसके सेवन से आप असमय बूढ़े नहीं होती है। साथ ही यह एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। ऐसे में कच्चे पपीते के सेवन से दाग-धब्बे और झुर्रियों आदि की समस्या नहीं होती है। इसके साथ ही खुजली, इर्रिटेशन, इंफ्लेमेशन, त्वचा पर होने वाली जलन को भी कम करने में सहायक है।

• कई रिसर्चों में सामने आया है कि यदि आप रोजना कच्चे पपीते का सेवन करते हैं, तो इससे कोलन और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी हद तक कम होता है। क्योंकि इसमें मौजूद फीटोन्यूट्रिएंट्स, एंटी-ऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉयड्स हमारे शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकते हैं।

• इसके अलावा इसमें फाइबर पाया जाता है, जो आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। जो लोग कब्ज, बदहजमी, अपच, गैस जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। उनको कच्चे पपीते का सेवन आप सब्जी, सूप, सलाद, हलवा, फ्रूट स्मूदी आदि के तौर पर करना चाहिए।

• आज के समय में हर तीसर व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है। ऐसे में अगर आप भी अपने वेट कम करता चाहते हैं तो कच्चा पपीता इसमें आपकी मदद कर सकता है। कच्चे पपीते के सेवन से शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है। आप चाहें तो कच्चे पपीते को कदूकस कर के दही के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। या फिर इसे सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं।

• अक्सर महिलाओं में यूरिन इंफेक्शन की समस्या हो जाती है। ऐसे में कच्चा पपीता यूरिन इंफेक्शन की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। कच्चा पपीता इंफेक्शन को खत्म कर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने में सहायक होता है।

इन आईशैडो हैक्स की मदद से आंखों को बनाएं ब्यूटीफुल

आजकल आईशैडो लगाते समय डिफरेंट शेड्स को आई मेकअप का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि वे डिफरेंट कलर्स को आईशैडो में कैसे शामिल लें। इसके लिए आप इस हैक की मदद लें। आईमेकअप करते समय महिलाएं सबसे ज्यादा अपनी आंखों पर फोकस करती हैं। आई मेकअप आपके लुक को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। आई मेकअप के दौरान आईशैडो को लगाना काफी मुश्किल होता है। बहुत कम लड़कियां होती हैं, जो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से लगा पाती हैं। ऐसे में उन्हें आईशैडो से मनचाहा लुक नहीं मिल पाता और यही कारण है कि बहुत सी लड़कियां आई मेकअप के दौरान आईशैडो को स्किप कर देती हैं।

रखें इसका ध्यान

आजकल आईशैडो लगाते समय डिफरेंट शेड्स को आई मेकअप का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि वे डिफरेंट कलर्स को आईशैडो में कैसे शामिल लें। इसके लिए आप इस हैक की मदद लें। मेकअप एक्सपर्ट बताते हैं कि हमेशा आप डार्क शेड को हमेशा आईलिड के आउटर कार्नर पर लगाएं।

लगाएं प्राइमर

पाउडर आईशैडो लगाते समय अक्सर वह झड़ता है। साथ ही अधिकतर मामलों में एक आई लिड पर अधिक आईशैडो तो दूसरी लिड पर कम लग जाता है। ऐसे में अगर आप आईशैडो की एक इवन लेयर लगाना चाहती हैं तो ऐसे में आप पहले आईप्राइमर लगाएं। मेकअप एक्सपर्ट के अनुसार, आईप्राइमर लगाकर आप परफेक्ट आईशैडो लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास आईप्राइमर नहीं है तो आप फाउंडेशन को भी लिड पर एक बेस की तरह लगा सकती हैं। इसके बाद ही आईशैडो लगाएं।

टेप की लें मदद

ब्यूटी एक्सपर्ट के अनुसार, यह टिप बिगनर्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आईशैडो लगाते समय एक समस्या यह भी होती है कि एक साइड से वह थोड़ा बाहर निकल जाता है या फिर आईशैडो की शेप बिगड़ा जाती है। अगर आप भी बिगनर हैं और आईशैडो लगाते समय आप यह गलती करती हैं, तो ऐसे में आप टेप की मदद ले सकती हैं। इसके लिए आप टेप को अपने आउटर कार्नर पर क्रॉस करते हुए टेप लगाएं और उसके बाद आप आईशैडो लगाएं।

बनाएं आईलाइनर

आई मेकअप के दौरान आईलाइनर को अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर आप आईमेकअप से एक साफट लुक चाहती हैं तो ऐसे में आप लिक्विड लाइनर को स्किप करें और इसकी जगह आईशैडो का यूज करें। बस आप एक थिन एंगल्ड ब्रश लें और एक डार्क शेड के आईशैडो को उस पर लेकर बतौर आईलाइनर अप्लाई करें।

इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली हल्दी के है ढेरों स्वास्थ्य लाभ...

आयुर्वेद में हल्दी को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हल्दी के सेवन से आपके रक्त में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। हल्दी के औषधीय गुणों से हर कोई वाकिफ है और आजकल तो वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हल्दी के सेवन की सलाह दे रहे हैं। हल्दी में ढेर सारे गुण होते हैं। यह त्वचा की रंगत निखारने से लेकर दर्द से राहत और सर्दी-खांसी से छुटकारा दिलाने में बहुत मददगार होता है। खांसी और दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए विशेषज्ञ इसे रामबाण मानते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्ग चोट लग जाने या सर्दी-खांसी होने पर अक्सर हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते होंगे, साथ ही सदियों से रंग निखारने के लिए हमारे यहां हल्दी का उबटन लगाने की परंपरा है, लेकिन अब तो हेल्थ एक्पर्ट्स भी हल्दी वाला दूध पीने और हल्दी के पानी से गरारे की सलाह दे रहे हैं। दरअसल, कोरोना वायरस से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट करने में हल्दी भी बहुत मददगार है। यह वजह है कि विशेषज्ञ भी लोगों को हल्दी का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक, हल्दी में ढेर सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं तो आपको दर्द से राहत दिलाने के साथ ही इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है।

दिल को स्वस्थ रखता है

आयुर्वेद में हल्दी को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हल्दी के सेवन से आपके रक्त में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। यह रक्त को गाढ़ा नहीं होने देता जिससे धमनियों में रक्त प्रवाह सुचारु रूप से होता रहता है और दिल संबंधी बीमारियों नहीं होती। रक्त गाढ़ा होने से हार्ट अटैक और दिल संबंधी अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एक अध्ययन के अनुसार, हल्दी दूध के सेवन से सर्जरी के बाद आने वाले हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है।

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में में गुम हुआ उर्वशी रोतेला का फोन

24 कैरेट गोल्ड से बना था आईफोन

बीती रात अभिनेत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखने गई थी। यहाँ उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन गुम गया। इस बात की जानकारी उर्वशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दर्शकों को दी है। इसी के साथ अभिनेत्री ने फोन मिलने पर उनसे संपर्क करने की भी बात कही है। बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। अभिनेत्री की चर्चा की वजह उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन है, जो बीती रात गुम हो गया है। दरअसल, बीती रात अभिनेत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखने गई थी। यहाँ उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन गुम गया। इस बात की जानकारी उर्वशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दर्शकों को दी है। इसी के साथ अभिनेत्री ने फोन मिलने पर उनसे संपर्क करने की भी बात कही है।

उर्वशी रौतेला बीती रात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची थी। इस दौरान उनका 24 कैरेट गोल्ड आईफोन गुम हो गया। अभिनेत्री ने फोन गुम होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। उर्वशी ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में मेरा 24 कैरेट असली सोने का आईफोन खो गया! अगर किसी को यह मिले तो कृपया मदद करें।' इसके साथ ही उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी है।

अरबपति निखिल कामथ को डेट कर रही हैं रिया चक्रवर्ती

खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री इन दिनों बिजनेसमैन निखिल कामथ के साथ रिश्ते में हैं। हालाँकि, रिया की तरफ से अभी तक निखिल के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की गयी है। लेकिन बीती रात अभिनेत्री के निखिल के साथ पार्टी में आने के बाद अफवाहों ने आग पकड़ ली है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री इन दिनों बिजनेसमैन निखिल कामथ के साथ रिश्ते में हैं। हालाँकि, रिया की तरफ से अभी तक निखिल के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की गयी है। लेकिन बीती रात अभिनेत्री के निखिल के साथ पार्टी में आने के बाद अफवाहों ने आग पकड़ ली है। सोशल मीडिया पर दोनों लव-बड्र्स की तस्वीरें छायी हुई हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं रिया के नए बॉयफ्रेंड कौन है और क्या काम करते हैं।

बीती रात रिया चक्रवर्ती को उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ के साथ एक पार्टी में स्पॉट किया गया। इस दौरान अभिनेत्री निखिल की गाडी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थीं। वहीं, निखिल ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। दोनों लव-बड्र्स को ट्विनिंग करते हुए देखा गया। अभिनेत्री ने पार्टी के लिए ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस का चुनाव किया था। वहीं उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने कैजुअल लुक चुना था। पार्टी से रिया और निखिल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छायी हुई है। बीती रात साथ में स्पॉट होने के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते में होने की चर्चा गर्म है।

निखिल कामथ भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। उन्होंने साल 2010 में अपने भाई नितिन कामथ के मिलकर भारत की सबसे बड़ी स्टॉक-ब्रोकिंग फर्मों में से एक जेरोधा (Zerodha) की शुरुआत की थी। निखिल और उनके भाई की संयुक्त कुल संपत्ति 45,754.5 करोड़ है। इसके अलावा बात करें तो रिया से पहले निखिल का नाम पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के साथ भी जुड़ चुका है। मानुषी और निखिल ने कथित तौर पर 2021 में डेटिंग शुरू की थी। दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा था। हालाँकि, डेटिंग के दौरान कई मौकों पर दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था। बता दें, फीफा विश्व कप के दौरान मानुषी और निखिल कतर के लुसैल स्टेडियम में साथ में स्पॉट हुए थे।

आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म 'सितारे ज़मीन पर' की घोषणा

2007 में दर्शील सफ़ारी और आमिर खान ने 'तारे ज़मीन पर' से एक ब्लॉकबस्टर हिट दी। यह फिल्म, जो आमिर के निर्देशन में पहली फिल्म थी, ने 8 वर्षीय डिस्लेक्सिक बच्चे ईशान के जीवन और कल्पना का पता लगाया।

आमिर खान ने अब अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है जिसका नाम 'सितारे जमीन पर' है। अभिनेता ने कहा कि यह उनकी 2007 की फिल्म 'तारे जमीन पर' के समान होगी। 2007 में दर्शील सफ़ारी और आमिर खान ने 'तारे ज़मीन पर' से एक ब्लॉकबस्टर हिट दी। यह फिल्म, जो आमिर के निर्देशन में पहली फिल्म थी, ने 8 वर्षीय डिस्लेक्सिक बच्चे ईशान के जीवन और कल्पना का पता लगाया। उन्होंने फिल्म का निर्देशन करने के अलावा इसमें अभिनय भी किया। अमोल गुप्ते द्वारा लिखित इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आमिर खान ने अब अपनी आने वाली फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका नाम 'सितारे जमीन पर' है। अभिनेता ने बताया कि फिल्म की थीम 'तारे जमीन पर' से मिलती-जुलती है।

'लाल सिंह चड्ढा' की असफलता के बाद अब आमिर खान ने अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में आमिर ने कहा, ''मैंने इस बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है और अब भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं शीर्षक बता सकता हूं। फिल्म का नाम 'सितारे जमीन पर' है। आपको मेरी फिल्म 'तारे जमीन पर' तो याद ही होगी और इस फिल्म का नाम है 'सितारे जमीन पर' क्योंकि हम उसी थीम के साथ 10 कदम आगे बढ़ रहे हैं। 'तारे ज़मीन पर' एक इमोशनल फिल्म थी। ये फिल्म आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। उस फिल्म ने आपको रुलाया, यह आपका मनोरंजन करेगी।'

आमिर ने आगे कहा, 'लेकिन थीम एक ही है। इसलिए हमने बहुत सोच-समझकर यह नाम रखा। हम सभी में खामियां हैं, हम सभी में कमजोरियां हैं, लेकिन हम सभी में कुछ खास भी है, इसलिए हम इस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार, उस फिल्म में विशेष बच्चे ईशान का किरदार - मेरा किरदार 'तारे ज़मीन पर' में उस किरदार की मदद करता है। 'सितारे ज़मीन पर' में, वे नौ लड़के मेरी मदद करते हैं, जिनकी अपनी समस्याएं हैं।

साइबर ठगी का शिकार हुए आफताब शिवदासानी

अभिनेता को लगी लाखों रुपयों की चपत

सोशल मीडिया के विकास के साथ साइबर धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कभी-कभी सेलिब्रिटीज भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता आफताब शिवदासानी शिकार बन गए और उन्होंने केवाईसी धोखाधड़ी में बड़ी रकम गंवा दी।

सोशल मीडिया के विकास के साथ साइबर धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कभी-कभी सेलिब्रिटीज भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता आफताब शिवदासानी शिकार बन गए और उन्होंने केवाईसी धोखाधड़ी में बड़ी रकम गंवा दी। एक रिपोर्ट के अनुसार, आफताब शिवदासानी को एक टेक्स्ट संदेश मिला जिसमें उनसे एक निजी बैंक से जुड़े अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) विवरण अपडेट करने के लिए कहा गया। घटना रविवार को हुई और बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अभिनेता को एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें केवाईसी विवरण बैंक से लिंक नहीं होने पर बैंक खाता निलंबित करने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने आगे लिंक पर क्लिक किया और निर्देशों का पालन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद, उन्हें एक डेबिट संदेश मिला जिसमें कहा गया कि उनके बैंक खाते से 1,49,999 रुपये डेबिट कर लिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं, 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रैंप वॉक के बाद पागल कहे जाने पर भड़कीं सबा...

फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित बहुप्रतीक्षित बायोपिक सैम बहादुर का टीज़र शुक्रवार को निर्माताओं द्वारा जारी किया गया। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार ने इंस्टाग्राम पर विक्की कौशल अभिनीत आगामी फिल्म का पहला टीज़र साझा किया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित बहुप्रतीक्षित बायोपिक सैम बहादुर का टीज़र शुक्रवार को निर्माताओं द्वारा जारी किया गया। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार ने इंस्टाग्राम पर विक्की कौशल अभिनीत आगामी फिल्म का पहला टीज़र साझा किया। कैप्शन में उन्होंने हिंदी में लिखा, ''जिंदगी उनकी, इतिहास हमारा।''

रीमा कागती और रुचिका ओबेरॉय द्वारा निर्देशित 'दहाड़' में सोनाक्षी सिन्हा, विजय वर्मा, गुलशन देवैया और सोहम शाह हैं। इस शो का प्रीमियर 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। फिल्म को प्रशंसकों और आलोचकों से अच्छी समीक्षाएं मिलीं। इस बीच, विजय वर्मा ने प्राइम वीडियो शो में सीरियल किलर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - भारत का पुरस्कार जीता है

अक्षय को क्यों लेनी पड़ी थी कनाडा की नागरिकता?

हाल ही में भारतीय नागरिकता पाने वाले अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता लेने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अक्षय ने खुलासा किया कि वह कनाडाई बन गए क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं और उन्होंने 13 से 14 फ्लॉप फिल्में दीं।

हाल ही में भारतीय नागरिकता पाने वाले अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता लेने के पीछे की असली वजह का खुलासा किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अक्षय ने खुलासा किया कि वह कनाडाई बन गए क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं और उन्होंने 13 से 14 फ्लॉप फिल्में दीं। 56 वर्षीय अभिनेता ने एएनआई को बताया, ''उस समय, मेरा दोस्त कनाडा में रहता था और उसने कहा कि तुम यहां आओ और हम कुछ पर काम करेंगे। मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर दिया था कि हम साथ मिलकर कार्गो बिजनेस करेंगे। मैंने कहा ठीक है मेरी फिल्में भी अच्छी नहीं चल रही हैं और इंसान को काम तो करना ही पड़ता है, चाहे वह कहीं भी हो। जब मैं टोरंटो में रहने लगा तो मुझे कनाडा का पासपोर्ट मिल गया।''

इस बारे में बात करते हुए कि कैसे उन्होंने अपना मन बदला और भारत में ही रुके रहे, उन्होंने कहा, ''उस बीच, दो फिल्में रिलीज के लिए बाकी थीं। दोनों फिल्में रिलीज होने के बाद काफी सुपरहिट हो गईं। मैंने उससे कहा कि मैं वापस जा रहा हूं. फिर मुझे और फिल्में मिलीं और आज यहां तक पहुंच गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग इस पर

कब्जा कर लेंगे, यह सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज़ था। मैं सिर्फ अपना कर चुकाता हूं और मैं सबसे बड़ा करदाता हूं।''

भारतीय नागरिकता मिलने पर उन्होंने कहा कि कई सालों से वह वहां नहीं गए और उनका एक सबसे अच्छा दोस्त भी कनाडा में रहता है। उन्होंने कहा कि ''9-10 साल तक मैं वहां नहीं गया। यह बहुत अच्छी जगह है और मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक वहां है। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपनी नागरिकता ले लेनी चाहिए। यह महज संयोग था कि 15 अगस्त को मुझे पत्र मिला कि मुझे नागरिकता मिल गयी है। लेकिन यह सिर्फ एक पासपोर्ट नहीं है, यह आपका दिमाग है, यह आपका दिल है, यह आपकी आत्मा है जिसे भारतीय होना होगा। अगर मेरे पास भारतीय पासपोर्ट तो है लेकिन मेरी आत्मा, दिमाग और दिल भारतीय नहीं है तो इसका क्या मतलब है?'' 15 अगस्त को भारत की नागरिकता मिलने के बाद अक्षय कुमार ने एक खास पोस्ट शेयर किया था और लिखा था, ''दिल और नागरिकता, दोनों हिंदुस्तानी.'' स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! जय हिन्द।''

मनोज चतुर्वेदी संपादक और निरंजन शर्मा एडिशनल एस पी ग्वालियर ग्रामीण

पद्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णागरुप्रचुरचन्दनचर्चिताय।
भस्मानुषक्तविकचोत्पलमल्लिकाय नीलाब्जकण्ठसदृशाय नमः शिवाय।।

अर्थात : जो स्वच्छ पद्मरागमणि के कुण्डलों से किरणों की वर्षा करने वाले हैं, चन्दन तथा अगरू से चर्चित तथा भस्म, जूही से सुशोभित और प्रफुल्लित कमल ऐसे नीलकमलसदृश कण्ठवाले शिव शंकर को प्रणाम।